My Notes…..

राष्ट्रीय

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि **निजता एक मौलिक अधिकार है।** निजता राइट टू लाइफ का हिस्सा है। निजता के हनन करने वाले कानून गलत हैं। कोर्ट ने कहा कि **निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह संविधान के आर्टिकल 21 (जीने के अधिकार) के तहत आता है।** मामले में बहस के बाद कोर्ट ने गत दो अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब पांच न्यायाधीशों की पीठ आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

क्या है

1. निजता के अधिकार पर बहस इसलिए शुरू हुई, क्योंकि **आधार योजना को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलील है कि बायोमीट्रिक डाटा और सूचनाएं एकत्र करने से उनके निजता के अधिकार का हनन होता है।**
2. **सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व फैसलों में आठ न्यायाधीशों** और छह न्यायाधीशों की पीठ कह चुकी है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसे में **भारत सरकार और याचिकाकर्ताओं ने निजता के अधिकार** का मुद्दा बड़ी पीठ के द्वारा सुने जाने की अपील की थी। इस पर नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित हुई।
3. **पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर हैं।** उनके अलावा पीठ में जस्टिस जे. चेलमेश्वर, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

विरोध में सरकार की दलीलें

1. **ये सन्निहित अधिकार है,** लेकिन ये कॉमन लॉ में आता है।
2. निजता हर मामले की परिस्थितियों पर तय होती है।
3. संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर इसे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया था।
4. कोर्ट मौलिक अधिकार घोषित करता है, तो यह संविधान संशोधन होगा जिसका कोर्ट को अधिकार नहीं है।
5. आंकड़े एकत्रित करना निजता के तहत नहीं आता।
6. निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया, तो तकनीक का सहारा लेकर गुड गर्वनेंस के प्रयास रुक जाएंगे।

पृष्ठभूमि

1. आजादी से पहले भी राइट टू प्राइवेसी की वकालत जोरदार ढंग से होती रही है। **1895 में लाए गए भारतीय संविधान बिल में भी राइट टू प्राइवेसी की वकालत सशक्त तरीके से की गई थी।** इस बिल में कहा गया था कि हर व्यक्ति का घर उसकी शरणस्थली होता है और सरकार बिना किसी ठोस कारण और कानूनी अनुमति के उसे भेद नहीं सकती।
2. इसके बाद **1925 में महात्मा गांधी की सदस्यता वाली समिति ने कामनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल** को बनाते हुए भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख किया था।
3. मार्च 1947 में भी भीमराव आंबेडकर ने राइट टू प्राइवेसी के विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा था कि लोगों को अपनी निजता का अधिकार है।
4. इस **अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कड़े मापदंड तय करने की जरूरत थी।** मगर उनका यह भी कहना था कि अगर किसी कारणवश उसे भेदना सरकार के लिए जरूरी हो तो सबकुछ न्यायलय की कड़ी देख रेख में होना चाहिए।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

7. समर्थन में याचिकाकर्ताओं की दलीलें
8. निजता सम्मान से जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
9. मुख्य अधिकार मौलिक अधिकार है, तो उसका हिस्सा भी माना जाएगा।
10. कोर्ट कई फैसलों में निजता के अधिकार को मान्यता दे चुका है।
11. निजता को स्वतंत्रता व जीवन के अधिकार से अलग करके नहीं देख सकते।
12. अमेरिका और अन्य देशों में निजता को मौलिक अधिकार माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तीन तलाक

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही **तीन तलाक गैरकानूनी हो गया है** और इसे तीन बार कहने से निकाह खत्म नहीं होगा। **पांच जजों की संविधान पीठ** में जस्टिस कुरियन जोसेफ, आरएफ नरीमन, जस्टिस यूयू ललित ने 3-2 के बहुमत से तीन तलाक को **बराबरी के अधिकार वाले अनुच्छेद 14, 15 के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया।**

क्या है

1. तीनों जजों ने कहा कि **1937 के मुस्लिम शरीयत कानून के तहत तलाक को धारा 2 में मान्यता दी गई है** और उसकी विधि बताई गई है। चूंकि यह कानून के रूप में था, इसलिए यह संवैधानिक सिद्धांतों की जांच के दायरे में आएगा।
2. **संविधान के सिद्धांतों को देखते हुए तीन तलाक स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है।** इसलिए इसे सिरे से रद्द किया जाता है।
3. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार शीर्ष अदालत ने 3-2 के मत से सुनाए गए फैसले में इस तीन तलाक को कुरान के मूल तत्व के खिलाफ बताया।
4. जस्टिस कुरियन ने कहा कि वह तीन तलाक को धर्म का हिस्सा मानने के सीजेआई के मत से सहमत नहीं हैं। यह धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का तीन तलाक को गैरकानूनी मानने वाला शमीमआरा फैसला सही कानून घोषित करता है और वह उसे बरकरार रखते हैं। जो धर्म में गलत है वह कानून में सही नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ता और पक्ष की दलील

1. तीन तलाक को खत्म करने के लिए याचिकाएं मुस्लिम महिलाएं **शायरा बानो, फराह फैज, आफरीन रहमान, इशरत जहां और गलशन परवीन** ने दायर की थीं। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने इनका विरोध किया था।
2. उसने कहा था कि **सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।** हालांकि बाद में बोर्ड ने कहा था कि वह काजियों को एडवाइजरी जारी करेगा कि वे विवाह करने वालों को सलाह देंगे कि तीन तलाक के जरिये विवाह को समाप्त न करें।
3. केंद्र सरकार ने महिलाओं का पक्ष लिया था और कहा था कि तीन तलाक महिलाओं के खिलाफ अन्याय है और धर्म का मौलिक अंग नहीं है।

CSIR को विश्व के सरकारी संस्थानों में स्थान

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को विश्व के सरकारी वैज्ञानिक संस्थानों में नौवां स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि, विश्व के टॉप 100 संस्थानों में (सरकारी एवं निजी) में सीएसआईआर को 75वां स्थान है। टॉप 100 वैज्ञानिक संस्थानों में जगह पाने वाला **सीएसआईआर देश का पहला वैज्ञानिक संस्थान है।**

क्या है

1. **शिमागो इंस्टीट्यूसंश रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2017 के** अनुसार **विश्व के कुल 1207 सरकारी वैज्ञानिक संस्थानों में सीएसआई को नौवां स्थान मिला है।**
2. पहले आठ स्थानों पर **चीन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रूस, जापान और इटली के वैज्ञानिक संस्थान हैं।**
3. इस रैंकिंग में गैर सरकारी वैज्ञानिक संस्थानों को मिलाकर कुल 5250 संस्थानों की रैंकिंग की गई है। इसमें भी **सीएसआईआर ने 75वां स्थान हासिल किया है।**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

4. शिमागो वैज्ञानिक संस्थानों की प्रयोगशालाओं में उपलब्ध संसाधनों के आकलन, इनोवेशन, प्रकाशित हुए शोधपत्रों, विकसित की गई तकनीकों और तकनीकों के व्यवसायीकरण की सफलता के आधार पर रैंकिंग देता है।
5. **पिछले साल 12वें स्थान पर थी :** सीएसआईआर की **देश भर में कुल 38 प्रयोगशालाएं हैं,** जिनमें कई महत्वपूर्ण शोध हो रहे हैं।

सतत विकास लक्ष्यों के लिए डेटा सृजन

एसडीजी के लिए महिला-पुरुष संकेतकों से जुड़े डेटा के सृजन और डेटा के उपयोग हेतु एक खाका (रोडमैप) तैयार करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों और उनके सांख्यिकीय समकक्षों के साथ-साथ बड़ी संख्या में विभिन्न भागीदारों के बीच भी घनिष्ठ सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने योग्य कदमों को तलाशने के लिए **एमओएसपीआई नई दिल्ली में 21-22 अगस्त, 2017 को 'यूएन वूमन' के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों के महिला-पुरुष संकेतकों के लिए डेटा सृजन** पर दो दिवसीय राष्ट्रीय मंत्रणा का आयोजन करने जा रहा है। इस मंत्रणा से एसडीजी के लिए महिला-पुरुष संकेतकों में अंतर को दूर करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा जिससे डेटा के सृजन और डेटा उपयोग के स्वामित्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, बहु-हितधारक मंत्रणा से महिला-पुरुष से जुड़े आंकड़ों के बारे में सहयोग बढ़ाने के लिए एक सामान्य समझ और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य **एसडीजीहेतु महिला-पुरुष संकेतकों के लिए डेटा सृजन पर ठोस कदमों का एक रोडमैप तैयार करने के लिए विचारों को इकट्ठा करना है।**

पृष्ठभूमि

1. भारत वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित **'ट्रांसफॉर्मिंग ऑवर वर्ल्डः द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' संकल्प (2030 एजेंडा)** पर एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
2. इस **2030 एजेंडे में 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 लक्ष्य शामिल हैं।** जहां एक ओर लक्ष्य **5 'महिला-पुरुष समानता हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने' से जुड़ा एकल लक्ष्य है,** वहीं दूसरी ओर पूरे ही एजेंडे में महिला-पुरुष समानता को मुख्यधारा में लाया गया है।
3. संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के सांख्यिकीय कार्यालयों एवं मुख्य एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा एसडीजी संकेतकों पर गठित अंतर-एजेंसी एवं विशेषज्ञ समूह (आईएईजी-एसडीजी) के साथ सलाह-मशविरा करके 232 अनूठे संकेतकों के एक समूह पर वैश्विक स्तर पर सहमति बनी है।
4. वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क पर अमल को सुविधाजनक बनाने के लिए आईएईजी-एसडीजी द्वारा सभी संकेतकों को विधिवत विकास के उनके स्तर और डेटा के नियमित सृजन के आधार पर तीन श्रेणियों (टियर) में वर्गीकृत किया जाता है।
5. टियर 1 के संकेतकों के लिए कम से कम आधे देशों द्वारा डेटा को नियमित रूप से सृजित किया जाता है। टियर 2 के संकेतकों की अपनी एक स्थापित पद्धति है, लेकिन डेटा का नियमित रूप से सृजन नहीं होता है। वहीं, टियर 3 में ऐसे संकेतक हैं जिनके लिए कोई भी स्थापित पद्धति और मानदंड अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय मंत्रणा के उद्देश्य

1. **एसडीजी के लिए विजन 2030** हेतु महिला-पुरुष संकेतकों और महिला-पुरुष से जुड़े आंकड़ों की आवश्यकता के बारे में सामाजिक क्षेत्र संबंधी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अवगत कराना।
2. एसडीजी के लिए महिला-पुरुष से जुड़े राष्ट्रीय संकेतकों की निगरानी हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के हितधारकों के साथ आगे बढ़ने की राह पर चर्चा करना।
3. **एसडीजी के लिए महिला-पुरुष से जुड़े संकेतकों से जुड़े डेटा के संग्रह** या उपयोग या प्रसार पर नवीनतम सर्वोत्तम विधियों को साझा करके सहयोगात्मक अध्ययन और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।

भारत में प्रगति

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

1. **एसडीजी 5 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) को मुख्य मंत्रालय के रूप में चिन्हित किया गया है।**
2. विभिन्न अन्य मंत्रालयों जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी, भूमि संसाधन विभाग), आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओयूडी), आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की भी पहचान ऐसे मंत्रालयों के रूप में की गई है जो महिला-पुरुष संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) भारत के लिए वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क को प्रासंगिक बनाने में जुटा हुआ है। मंत्रालय ने व्यापक सलाह-मशविरा के लिए एसडीजी से जुड़े राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के मसौदे को सार्वजनिक तौर पर पेश किया है, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

आईआरएनएसएस-1एच मिशन असफल

पहली बार प्राइवेट कंपनियों की मदद से अंतरिक्ष की दुनिया में एक और छलांग लगाने की इसरो की कोशिश असफल रही। श्रीहरिकोटा से 31 अगस्त की शाम सात बजे जिस **स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलेइट सिस्टम (आईआरएनएसएस यानि नाविक) श्रृंखला का आठवां उपग्रह आईआरएनएसएस-1एच को पीएसएलवी-सी39 से लांच किया गया** वो सफल नहीं हो पाया। ये जानकारी इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने दी। आइये बताते है कि ये किसलिए अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के लिए एक लंबी छलांग मानी जा रही थी।

क्या है

1. **1425 किलोग्राम भार वाले आईआरएनएसएस-1एच** इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का **आठवां सैटेलाइट था जो आईएरएनएसएस-1ए की जगह लेता,** जिसकी **तीन रूबीडियम परमाणु घड़ियों (एटॉमिक क्लॉक) ने काम करना बंद कर दिया था।**
2. आईआरएनएसएस-1ए 'नाविक' श्रृंखला के सात उपग्रहों में शामिल हैं। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे **भारत ने अमेरिका के जीपीएस की तर्ज पर विकसित किया है।**
3. **यह पहला मौका है जब किसी सैटलाइट को बनाने में प्राइवेट कंपनियां सीधे तौर पर शामिल हुई।** आईआरएनएसएस-1 एच को बनाने में **प्राइवेट कंपनियों का 25% योगदान रहा है।** ऐसा माना जा रहा था कि एक बार लॉन्च हो जाने के बाद अपनी लोकेशन बेस्ड सर्विस के जरिए आईआरएनएसएस रेलवे, सर्वे और दूसरी कई चीजों में काफी महत्वपूर्ण साबित होता।
4. बीते तीन दशकों में **इसरो के लिए यह पहला मौका है जब उसने नेविगशन सैटेलाइट बनाने का मौका निजी क्षेत्र को दिया है।** इसरो प्रमुख एएस किरण कुमार ने बताया कि हमने सैटेलाइट जोड़ने में निजी संस्थानों की मदद ली है। इसके लिए **रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाले बेंगलुरु के अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को पहला मौका मिला है।** 70 इंजीनियरों ने कड़ी मेहनत के बाद इस सैटेलाइट को तैयार किया है।
5. अगर इस उपग्रह की लॉन्चिंग सफल रहती तो इसी सीरीज के पहले उपग्रह **आईआरएनएसएस-वनए की जगह लेता। इसे एक जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था।**
6. **अमेरिका का जीपीएस, रूस का ग्लोनास** और **यूरोपीय संघ का गैलीलियो नेवीगेशन सिस्टम** ही ग्लोबल सेवाएं दे रहे हैं। **चीन का बीडू-1, जापान का क्यूजेडएसएस** फ्रांस का डोरिस मौजूदा क्षेत्रीय नेवीगेशन सिस्टम है। भारत ने 2016 में नाविक स्थापित कर विश्व में धाक जमा दी है।
7. **आईआरएनएसएस को नेवीगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन सिस्टम (जीपीएस) की तरह ही है।** लेकिन यह सिर्फ भारत और उसके चारों और **1500 किमी. के क्षेत्र में ही कार्य करता है।**
8. इसके तरहत 2013 से 2016 के बीच इसरो ने सात उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। इनमें से आईआरएनएसएस-1जी का प्रक्षेपण 28 अप्रैल 2016 को किया गया। आईआरएनएसएस-1एफ का प्रक्षेपण 10

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

मार्च 2016 को किया गया। आईआरएनएसएस-1ई का प्रक्षेपण 20 जनवरी 2016 को किया गया। आईआरएनएसएस-1डी का प्रक्षेपण 28 मार्च 2015 को किया गया। आईआरएनएसएस-1सी का प्रक्षेपण 16 अक्तूबर 2014 को किया गया। आईआरएनएसएस-1बी का प्रक्षेपण चार अप्रैल 2014 को किया गया और आईआरएनएसएस-1ए का प्रक्षेपण एक जुलाई 2013 को किया गया था। इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने, समुद्री जहाजों और अन्य वाहनों को रास्ता दिखाने, ट्रेन की लोकेशन बताने समेत कई क्षेत्रों में होता है।

9. **इंडियन रीजनल नेवीगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) एक स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रणाली है** जिसका विकास भारत ने अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लोनास तथा यूरोप द्वारा विकसित गैलिलियो के मुताबिक किया है।

नाविका सागर परिक्रमा

नाविका सागर परिक्रमा, एक अभियान है, जिसमें भारतीय नौसेना की **महिला अधिकारियों की एक टीम** भारत में निर्मित पाल नौका (सेल बोट) **आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर विश्व परिक्रमा करेगी।** यह पहला अवसर है, **जब सर्व-महिला चालक दल इस प्रकार की विश्व परिक्रमा करेगा।** यह यात्रा सितंबर 2017 के आरंभ में होने का कार्यक्रम है। **आईएनएसवी तारिणी, आईएनएसवी महादेई की सहयोगी पोत है।** यह परिक्रमा भारत सरकार की 'नारी शक्ति' पर बल देने की नीति को परिलक्षित करते हुए नौसेना में महासागर में नौकायन की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण समझा जा रही है।

क्या है

1. पहली बार एकल परिक्रमा कैप्टन दिलीप डोंडे, एससी (सेवा निवृत्त) द्वारा **19 अगस्त, 2009 से 19 मई 2009 तक भारत में निर्मित पोत आईएनएसवी महादेई** पर सवार होकर की गई थी। **पहली भारतीय अविराम(नॉन-स्टॉप) एकल परिक्रमा कमांडर अभिलाष टॉमी,** केसी द्वारा 01 नवम्बर, 2012 से 31 मार्च 2013 तक की गई थी।
2. इस सर्व महिला चालक दल को आगामी समुद्री यात्रा के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है।उन्होंने प्रशिक्षण के तहत आईएनएसवी महादेई और तारिणी पर लगभग 20,000 समुद्री मील नौकायन किया है, जिसमें मॉरिशस तक दो अभियान (2016 और 2017 में) तथा दिसंबर 2016 में गोवा से केपटाउन तक की समुद्री यात्रा शामिल है।

इस अभियान के अतिरिक्त लक्ष्य निम्नलिखित हैं -

1. नारी शक्ति
2. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
3. मेक इन इंडिया
4. मौसम/महासागर/वेव डेटा आब्जर्वेशन
5. समुद्री प्रदूषण
6. स्थानीय पीआईओ के साथ संवाद

3. **आईएनएसवी तारिणी 55 फुट लम्बी पाल नौका है,** जिसका निर्माण **मैसर्स एक्वेरियस शिपयार्ड प्रा. लिमिटेड, गोवा ने किया है।** तारिणी को भारतीय नौसेना में 18 फरवरी 2017 को शामिल किया गया।
4. यह पोत अब तक 8,000 समुद्री मील का सफर तय कर चुकी हैं। नाविका सागर परिक्रमा पांच चरणों में होगी। इस दौरान राशन और आवश्यक मरम्मत के लिए चार बंदरगाहों पर रूका जाएगा।
5. **इस अभियान को दिया गया 'नाविका सागर परिक्रमा' नाम बिल्कुल उपयुक्त है,** क्योंकि इसका लक्ष्य देश में महिला सशक्तिकरण तथा नौसेना में महासागर में नौकायन की गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत

तकरीबन दो महीने की **जद्दोजहद व तमाम कूटनीति दांवपेंच के बाद चीन को यह एहसास हो गया कि वर्ष 1962 के बाद से हालात काफी बदल गये हैं।** भारत का नजरिया भी बदल गया है और **सामरिक व कूटनीतिक ताकत भी बढ़ गई है।** इस एहसास का नतीजा है कि वह **भारत के साथ मिल कर सिक्किम-भूटान सीमा पर स्थित डोकलाम विवाद का समाधान निकालने को तैयार हो गया है।** दोनों देशों के बीच यह सहमति बन गई है कि विवादित स्थल से तैनात सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। देर शाम तक सैनिकों की वापसी का काम संपन्न भी हो गया। देशी विदेशी

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

जानकारों ने इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया है क्योंकि चीन डोकलाम में सड़क निर्माण कार्य नहीं कर सकेगा। भारत को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी से थी।

क्या है

1. डोकलाम का समाधान निकालने को लेकर बनी सहमति **ब्रिक्स शिखर बैठक के तकरीबन दस दिन पहले बनी है।** चीन में होने वाली इस बैठक में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। अगर डोकलाम विवाद यूं ही जारी रहता तो मोदी और **चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए ब्रिक्स शिखर बैठक करना या द्विपक्षीय वार्ता करना काफी असहज होता।** वैसे भारत ने पिछले दो महीनों में बेहद शांत लेकिन दृढ़ कूटनीति का नजारा दिया है जिसकी दूसरे देशों ने भी प्रशंसा की है। जबकि चीन की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी की जाती रही है।
2. भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि, **भारत व चीन पिछले कई दिनों से डोकलाम विवाद का कूटनीतिक समाधान निकलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं।** इस दौरान हमने अपनी चिंताओं व हितों से लगातार अवगत कराया है। इस आधार पर यह सहमति बनी है कि डोकलाम में जिस जगह पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं वहां से उन्हें अलग किया जाएगा।
3. विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि **डोकलाम निश्चित तौर पर भूटान और चीन के बीच का** मामला है। चीन के सैन्य बल पहले भी डोकलाम में पेट्रोलिंग करते रहे हैं जिसको लेकर भारत को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है।

कैसे शुरू हुआ था डोकलाम विवाद

1. डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। **यह एक ट्राई-जंक्शन है, जहाँ भारत, चीन और भूटान कि सीमा मिलती है।**
2. डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी सैन्य सीमा गतिरोध को संदर्भित करता है।
3. **18 जून, 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई,** जब करीब 300 से 270 भारतीय सैनिक दो बुलडोजर्स के साथ भारत-चीन सीमा पार कर पीएलए को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया।
4. 9 अगस्त, 2017 को, चीन ने दावा किया कि केवल 53 भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर अभी भी डोकलाम में हैं।
5. जबकि भारत ने इस दावे को नकारते हुये कहा था कि उसके अभी भी वहाँ करीब 300-350 सैनिक उपस्थित हैं।
6. **भौगोलिक रूप से डोकलाम भारत चीन और भूटान बार्डर के तिराहे पर स्थित है।** जिसकी भारत के नाथुला पास से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है। चुंबी घाटी में स्थित डोकलाम का महत्व भारत और चीन दोनों देशों के लिए बराबर माना जाता है।
7. 1988 और 1998 में चीन और भूटान के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश डोकलाम क्षेत्र में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे।
8. **वर्ष 2007 में इस मुद्दे पर एक नई दोस्ताना संधि हुई,** जिसमें भूटान के भारत से निर्देश लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया और यह वैकल्पिक हो गया।

4. **भारत की आपत्ति वहां सड़क निर्माण से जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा हितों को प्रभावित करते हैं।** अगर चीन वहां निर्माण कार्य नहीं करता है तो यह इस क्षेत्र में स्थाई शांति की सबसे बड़ी गारंटी है।
5. रणनीतिक व विदेशी मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है चीन आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह सकता कि वह डोकलाम से बाहर हो रहा है क्योंकि उसका इस पर दावा है।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

6. **नेशनल सिक्यूरिटी कालेज (आस्ट्रेलिया) के प्रोफेसर व हिंद प्रशांत क्षेत्र के विशेषज्ञ रोरी मेककाल्फ** के मुताबिक अगर चीन डोकलाम में सड़क नहीं बनाने को तैयार हो गया है तो यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।
7. मतलब है कि इन दिनों में चीन की ओर बहुत आक्रामक बयानबाजी होती रही है। जबकि **भारत की ओर से भी यह संदेश देने में चूक नहीं की गई कि भारत अब 1962 का देश नहीं है।**

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर कार्यबल का गठन

वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने **भारत के आर्थिक बदलाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर कार्यबल का गठन किया है।** वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास से **विश्व को चौथी औद्योगिकी क्रांति देखने को मिलेगी।** उन्होंने कहा कि **विशाल डाटा, उच्च गणन क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और एनालिटिक्स** से प्रेरित उद्योग का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र का डिजिटिकरण करना है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कार्यबल में विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, शोधकर्ता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि रखे गए हैं। यह **कार्यबल विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से मिलने वाले लाभ पर विचार करेगा।**

टास्क फोर्स के निम्नलिखित (सदस्य) होंगे

1. डॉ. वी कामकोटी, आईआईटी मद्रास (अध्यक्ष)
2. श्री अनुज कपूरिया, हाई टेक रोबोटिक सिस्टम्स लिमिटेड ((सदस्य))
3. डॉ. अनुराग अग्रवाल, जीनोमिक्स और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान, सीएसआईआर (सदस्य)
4. डॉ. आशीष दत्ता, आईआईटी कानपुर (सदस्य)
5. सुश्री अश्विनी अशोकन, मैड स्ट्रीट डेन, चेन्नई (सदस्य)
6. श्री गौतम श्रॉफ, उपाध्यक्ष एवं मुख्य वैज्ञानिक, टीसीएस इनोवेशन लैब्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, गुड़गांव (सदस्य)
7. श्री जी एच राव, एचसीएल टेक्नोलॉजी (सदस्य)
8. श्री जी मधुसूदन, आईआईटी मद्रास (सदस्य)
9. श्री जी वी एन अप्पाराव, पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), कॉग्निजेंट (सदस्य)
10. सुश्री कोमल शर्मा तलवार, संस्थापक, एक्सएलपीएटी (सदस्य)
11. श्री कुणाल नंदवानी, यूट्रेड सॉल्यूशंस के संस्थापक और सीईओ (सदस्य)
12. डॉ. शांतनु चौधरी, आईआईटी दिल्ली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग (सदस्य)
13. श्री विजय कुमार संकरापुर, आर्य. इन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सदस्य)
14. श्री अजय कुमार, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सदस्य)
15. श्री अमानदीप गिल, राजदूत/ पीआर से सीडी, जिनेवा (सदस्य)
16. श्री के नागराज नायडू, संयुक्त सचिव (आईटीपीओ), आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय (सदस्य)
17. डॉ. आलोक मुखर्जी, डीआरडीओ (सदस्य)
18. श्री रविंदर, संयुक्त सचिव, डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (संयोजक)

निम्नलिखित संगठनों से आधिकारिक भागीदारी का भी अनुरोध किया जाएगा:

1. नीती आयोग,
2. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
4. यूआईडीएआई
5. डीआरडीओ

'मेंटर इंडिया' अभियान

नीति आयोग "मेंटर इंडिया" अभियान शुरू करेगा। अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में **देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबो में छात्रों के मार्गदर्शन के काम मे अग्रणी भूमिका** निभाने वाले

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

लोगो को शामिल कर के यह राष्ट्र निर्माण की रणनीतिक पहल है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत 23 अगस्त को इस राष्ट्रव्यापी पहल की ऑनलाइन शुरुआत करेंगें। **मेंटर इंडिया अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है।** यह संभवत: विश्व भर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है। इसकी अवधारणा मे अग्रणी हस्तियों को इस अभियान से जोड़ना शामिल करना है जो अटल टिंकरिंग लैबों मे छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे लैब और ऐसे मेंटरों से आशा है कि वे प्रशिक्षक से ज्यादा मार्गदर्शक बनेंगें।

क्या है

1. नीति आयोग ऐसे अग्रणी लोगो की तलाश में है **जो कही भी प्रत्येक सप्ताह एक से दो घंटे के बीच एक या अधिक ऐसे लैबो में छात्रों को अनुभव लेने, सीखने तथा डिजाइन और गणनात्मक सोच** जैसे भविष्य के कौशलों के अभ्यास में समर्थ बनायेंगे।
2. **अटल टिंकरिंग लैब ऐसे वर्क स्टेशन हैं, जहाँ छठी कक्षा से ले कर बारहवीं कक्षा के छात्र नवीन कौशल सीखेंगे** और ऐसी अवधारणाएं विकसित करेंगे जिससे भारत की तस्वीर बदले। ये लैब छात्रों को थ्री डी प्रिंटरों, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स औजारों, इंटरनेट और सेंसरों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में जानकारी देंगे।
3. **नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन,** भारत सरकार के उन फ्लैगशिप कार्यकर्मो में से एक है जिससे देश भर में अटल टिंकरिंग लैबो की स्थापना होगी और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
4. इस अभियान के तहत देशभर में 900 से अधिक ऐसे लैबो की स्थापना हो चुकी है। अथवा होने वाली है इसका लक्ष्य वर्ष 2017 के अंत तक ऐसे 2000 लैब स्थापित करना है।

सौर ऊर्जा को सुलभ बनाने लिये दिशा-निर्देश

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ग्रिड से संयोजित सौर ऊर्जा आधारित बिजली कारखानों से बिजली खरीदने के लिये दर-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। सरकार ने इन्हें 3 अगस्त 2017 को अधिसूचित किया है। **ये दिशा-निर्देश विद्युत कानून, 2003 के अनुच्छेद 63 के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा आधारित नीलामी प्रक्रिया** के जरिये बिजली की दीर्घकालीन खरीद के लिये क्रेताओं से ऐसे ग्रिड से संयोजित सौर ऊर्जा बिजलीघरों (प्रोजेक्ट्स) **जिनकी क्षमता 5 मेगावाट या अधिक हो।**

इन दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित हैं:

1. **खरीद के जोखिमों को कम करने के लिये उत्पादन के दौरान आने वाली अड़चनों के लिये उत्पादन क्षतिपूर्ति:** सौर बिजली घरों के अनिवार्य रूप से काम करने की स्थिति पर जोर दिया गया है। उत्पादन क्षतिपूर्ति का प्रावधान खरीद में आने वाली निम्नलिखित अड़चनों के लिये किया गया है।:
2. **बैक-डॉउन** - पीपीए टैरिफ का न्यूनतम 50%
3. **ग्रिड की अनुपलब्धता** - अतिरिक्त उत्पादन की खरीद के जरिये क्षतिपूर्ति/त्वरित क्षतिपूर्ति
4. **पीपीए:** दर कम रखने को सुनिश्चित करने के लिये बिजली खरीद समझौते की न्यूनतम अवधि 25 वर्ष रखी गयी है। बिजली खरीद समझौते को एक तरफा समाप्त करने या बदलने की अनुमति नहीं है।
5. **परियोजना को तैयार करने और बिजली घरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिये:** भूमि से जुड़े मुद्दों, यातायात की सुगमता, मंजूरियों और देरी होने की दिशा में अतिरिक्त समय दिये जाने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया गया है।
6. असफल रहने पर उसके परिणामों की सुस्पष्ट व्याख्या की गयी है ताकि जोखिम को उत्पादनकर्ता और क्रेता के बीच समुचित रूप से बांटा जा सके। इसके लिये उत्पादन एवं क्रय से संबंधित असफलताओं एवं उसके परिणामों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
7. **सौर ऊर्जा की खरीद के लिये दर-आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया के नये दिशा-निर्देश खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बढ़ावा देंगे** साथ ही सस्ती बिजली के जरिये उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेंगे।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

8. **ये दिशा-निर्देश कामकाज में एकरूपता और मानकता लायेंगे साथ ही सौर ऊर्जा आधारित बिजली घरों से बिजली की खरीद में सभी संबंद्ध पक्षों के बीच जोखिम के बंटवारे के लिये ढांचा भी मुहैया करायेंगे।**
9. यह बिजली क्रेताओं के जोखिम को करने में मदद करेंगे ताकि इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके, परियोजनाओं को बैंकों के लिये आकर्षक बनाया जा सके और निवेशकर्ताओं के लाभ को बढ़ाया जा सके।

तैयार हुआ हैंगिंग ब्रिज

राजस्थान के कोटा में लंबे समय से निमार्णाधीन हैंगिग ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री 29 अगस्त को अपनी उदयपुर यात्रा में इस ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ब्रिज की खास बात यह है कि चम्बल नदी पर बने इस पुल में बीच में कोई खंभा नहीं है। दोनों किनारों पर बने खंभों पर तारों के जरिए इसे स्थिर किया गया है।

क्या है

1. **यह ब्रिज 1.4 किलोमीटर लंबा है** और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण कराया है। इस ब्रिज के निर्माण पर 277 करोड़ रुपये की लागत आई है।
2. **इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था।** यह ब्रिज कोटा की यातायात की समस्या को बहुत हद तक दूर कर देगा।
3. अभी तक कोटा-झालावाड़ और कोटा-बारां नेशनल हाइवे के भारी वाहन कोटा शहर के बीचों बीच से गुजरते थे। अब यह ब्रिज कोटा के लिए बाइपास का काम करेगा।

शैक्षिक संस्थानों के लिए 54 देशों का होगा अध्ययन

शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए देश की नजर अब दुनिया के उन 54 देशों के शैक्षणिक पैटर्न पर टिकी है, जिनके साथ **शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर करार है।** ऐसे में जो योजना बनाई गई है, उसके तहत दुनिया के इन देशों में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अच्छे कार्यक्रमों की जानकारी जुटाना है, **साथ ही उनकी अच्छी प्रैक्टिस को अपनाना है।** फिलहाल इसे लेकर जिन देशों के **शैक्षणिक पैटर्न** को ज्यादा तबज्जो दी जा रही है, उनमें वह देश है, **जिनके बच्चे बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष भारत आते है।**

क्या है

1. मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक **इस दिशा में आस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों के साथ कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है।**
2. **इस योजना के एक मकसद यह भी है कि अपने संस्थानों में ज्यादा से ज्यादा विदेशी बच्चों को आकर्षित कर सकें।** वैसे भी पिछले कुछ सालों में भारत में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशों छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। इसे लेकर मंत्रालय अपनी चिंता जता चुका है।
3. मंत्रालय ने हाल ही में **अपनी एक योजना के तहत देश के करीब 20 संस्थानों को विश्वस्तरीय मानक के तहत तैयार करने की योजना बनाई है।** इसमें करीब 10 सरकारी संस्थान और 10 निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान भी होंगे। इसके लिए मंत्रालय ने भारी-भरकम बजट का भी प्रावधान किया है।
4. **भारत के दुनिया के जिन प्रमुख देशों के साथ शैक्षणिक करार है,** उनमें **आस्ट्रेलिया, इजराइल, तंजानिया, श्रीलंका, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, जापान, यूके, कनाडा, मॉरीशस, जर्मनी, रुस, मलेशिया, ब्रिक्स देश, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे, ब्राजील आदि शामिल है।**
5. खासबात यह है कि जिन 54 देशों के साथ भारत के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास को लेकर करार है, उनमें ज्यादा देशों के साथ ही पिछले कुछ सालों में ही यह करार किया गया है।

"प्रजाति 205"

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने पूसा, नई दिल्ली में भा.कृ.अनु.प.-गन्ना प्रजनन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र करनाल द्वारा आयोजित ''भारत में मिठास क्रांति के सौ 100 वर्ष: प्रजाति 205 से प्रजाति 0238 तक" **(गन्ने की विभिन्न प्रजातियां) और "न्यू इंडिया मंथन संकल्प से सिद्धि" कार्यक्रम** में लोगों को सम्बोधित करते हुए

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

कहा कि वानस्पतिक (बोटनिस्ट) सर डा. वेंकटरमण के सहयोग से **देश की पहली अन्तरजातीय संकर प्रजाति (सेकेरम ऑफसिनेरम व सेकेरम स्पोंटेनियम का क्रॉस) "प्रजाति 205"** उपोष्ण जलवायु हेतु विकसित की, जिसे **वाणिज्यिक खेती के लिए 1918 में जारी किया गया।** इस हाइब्रिड के कारण उत्तर भारत में गन्ना उत्पादन में लगभग **50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई व इसने प्रचलित सेकेरम बारबरी** और सेकेरम साईनैन्सिस जैसी गन्ने की प्रजातियों को मात दी।

क्या है

1. **प्रजाति 205** के बाद **गन्ना प्रजनन संस्थान ने उपोषण जलवायु के लिये कई महत्वपूर्ण "गन्ना किस्मो" को विकसित की,** जिनका वर्चस्व काफी समय तक रहा। इसके बाद गन्ना प्रजनन संस्थान ने उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिये **"पहली अदभुत गन्ना किस्म प्रजाति 312"** वर्ष 1928 में विकसित की तथा उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिये **"पहली अदभुत गन्ना किस्म प्रजाति 419" वर्ष 1933 में विकसित की।**
2. पिछले तीन वर्षों से उनकी सरकार के आने के बाद **गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल में विकसित प्रजाति 0238 के पूरे उत्तर भारत में विस्तार के बाद,** इस क्षेत्र के हर राज्य में गन्ने की पैदावार तथा चीनी रिकवरी में सार्थक वृद्धि देखने को मिली है।
3. पिछले सीजन में **प्रजाति 0238 की उत्तर प्रदेश में 36 प्रतिशत, पजांब में 63 प्रतिशत, हरियाणा में 39 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 17 प्रतिशत व बिहार में 16 प्रतिशत** गन्ना क्षेत्रफल में खेती की गई।
4. **प्रजाति 0238 तथा प्रजाति 0118** पूरे उत्तर भारत की चीनी मिलों की पहली पंसद बन चुकी है। **प्रजाति 0238 से गन्ना किसान अधिक पैदावार प्राप्त कर रहै हैं** व चीनी मिलें अधिक चीनी प्राप्त कर रहीं हैं।

नई मेट्रो नीति को मंजूरी

देश के लगभग सभी राज्यों से मेट्रो रेल की बढ़ती मांग को देखते हुए **केंद्र सरकार ने एक नई समग्र मेट्रो नीति को मंजूरी दी है।** नई नीति में वित्तीय निवेश, प्रबंधन, संचालन, किराया, सवारियों की सुरक्षा, रखरखाव और संबंधित शहर की **जरूरतों के हिसाब से नये मानक तय किये गये हैं।** इसके लिए राज्यों को विकल्प भी सुझाये गये हैं।

क्या है

1. समूची मेट्रो रेल प्रणाली के संचालन के लिए सभी **राज्यों को एकीकृत मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी का गठन भी करना होगा।** ताकि जिन शहरों में मेट्रो रेल चलाने का प्रस्ताव आये वहां के बारे में अथारिटी तीसरे पक्ष से स्वतंत्र जांच कराने के बाद ही आगे बढ़े।
2. **नीति में निजी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के दरवाजे खोल दिए गए हैं।** राज्यों को मेट्रो से जुड़े इलाकों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के अलावा फीडर सेवाएं देनी होंगी। वाराणसी जैसे जिन शहरों की मेट्रो योजनाएं अभी मंजूर नहीं हुई हैं, उन्हें नई नीति के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने पड़ेंगे।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई **केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई।** वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बताया कि नई मेट्रो नीति में राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के साथ निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।
4. इसमें **केंद्रीय सहायता को निजी भागीदारी से जोड़ दिया गया है।** यह भागीदारी पूरे प्रोजेक्ट अथवा उसके हिस्सों (संचालन, स्वचालित किराया संग्रह, रखरखाव आदि) के लिए हो सकती है।
5. **नई नीति में मेट्रो लाइन के दोनों ओर पांच किलोमीटर के क्षेत्र में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए फीडर सेवाओं, पैदल व साइकिल ट्रैक आदि** के अलावा भविष्य के विकास का खाका तैयार करना जरूरी कर दिया गया है। मेट्रो की मंजूरी के लिए राज्यों को साबित करना होगा कि वह किस तरह बीआरटीएस, लाइट रेल, ट्राम या रीजनल रेल के मुकाबले बेहतर है।
6. नई मेट्रो नीति में शहरी जन परिवहन परियोजनाओं को महज ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मानने के बजाय शहरों के कायाकल्प की परियोजनाएं माना गया है। इस लिए **मौजूदा 8 फीसद फाइनेंशियल इंटरनल रेट आफ रिटर्न के बजाय 14 फीसद इकोनामिक इंटरनल रेट आफ रिटर्न का पैमाना तय किया गया है।**

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

7. राज्यों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना होगा कि स्टेशनों पर कामर्शियल/प्रापर्टी का विकास कैसे होगा तथा विज्ञापन आदि से कैसे कमाई की जाएगी। उन्हें किराया निर्धारण के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना भी करनी होगी।
8. पीपीपी प्रोजेक्ट में राज्यों को तीन तरह से केंद्रीय सहायता दी जाएगी : **वीजीएफ के जरिए, 10 फीसद एकमुश्त अनुदान तथा 50 फीसद इक्विटी भागीदारी।** आपरेशन एवं मेंटिनेंस में निजी भागीदारी के भी तीन मॉडल होंगे।
9. **अब तक देश में दिल्ली, बंगलूर, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जयपुर तथा गुरुग्राम समेत आठ शहरों में (कुल 370 किलोमीटर) मेट्रो परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं।** जबकि हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे तथा लखनऊ समेत पांच शहरों में मेट्रो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। **इस तरह कुल 13 परियोजनाओं पर फैसला हो चुका है।**
10. दूसरी ओर इतने ही शहरों में कुल 595 किलोमीटर लंबाई वाली मेट्रो परियोजनाओं की योजना या रूपरेखा तैयार हो रही है।
11. इनमें दिल्ली मेट्रो चरण-4, दिल्ली व एनसीआर, वाराणसी, इंदौर, कोच्चि चरण-2, ग्रेटर चंडीगढ़, रीजन मेट्रो, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुवनंतपुरम तथा कोजीकोड शामिल हैं।

अन्तरराष्ट्रीय

अफगानिस्तान की आजादी की सालगिरह

19 अगस्त को अफगानिस्तान ने अपनी आजादी की 98 वीं वर्षगांठ मनाई। टोलो न्यूज की खबर के अनुसार, अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रक्षा मंत्रालय के परिसर में **स्वतंत्रता मीनार में पुष्पांजलि दी।** इस अवसर पर **गनी ने युद्धग्रस्त देश में सुरक्षा बहाल करने और शांति स्थापित करने के लिए दिवंगत सुरक्षा बलों को भी श्रद्धांजलि दी।**

क्या है

1. देश भर में **तालिबान के विद्रोहियों और इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह** के हमलों से लगातार हिंसा बढ़ रही है।
2. इस दिन सुबह में ही शिक्षकों और युवाओं ने राष्ट्रीय झंडे के साथ काबुल की सड़कों पर मार्च निकाला।
3. देशभर के 34 प्रांतों में कड़े सुरक्षा के बीच ये समारोह मनाया गया।
4. **राजा अमानुल्ला खान के नेतृत्व में अफगानियों ने 19 अगस्त, 1919 को ग्रेट ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी।**

नई अफगानिस्तान नीति का भारत ने किया स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने **नई अफगान नीति का ऐलान कर दिया।** इस नई नीति में **जहां पाकिस्तान को अमेरिका से फटकार मिली है तो वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत से और पर मदद की मांग की है।** भारत की ओर से ट्रंप की नई अफगान नीति का स्वागत किया गया है।

क्या है

1. **भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से नई अफगानी नीति का स्वागत किया गया है।** विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत, आतंकवादियों को पनाहगाह और सीमा पार से अन्य प्रकार का सहयोग मुहैया कराए जाने के मुद्दों से निपटने के अमेरिकी राष्ट्रपति के संकल्प का स्वागत करता है।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने पूर्व में अमेरिकी मदद का भरपूर फायदा उठाया है लेकिन अब उसे आतंकियों को पनाह देने की वजह से बहुत कुछ खोने का तैयार रहना होगा।
3. इसके साथ ही ट्रंप ने भारत से अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने की भी अपील की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करेगा।

4. लेकिन भारत को इसके एवज में अमेरिका की अफगानिस्तान में और मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार के जरिए भारत बिलियन डॉलर कमा रहा है और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि **भारत, अफगानिस्तान में उसका साथी बने।**
5. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस देश हैं जिनके तनावपूर्ण रिश्ते एक संघर्ष में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू

उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते तनाव व चेतावनी के बावजूद दक्षिण कोरिया व अमेरिका ने 21 अगस्त को वार्षिक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू कर दिया। बता दें कि उत्तर कोरिया ने चेताया था कि इस अभ्यास से क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। प्योंगयांग ने **पिछले महीने दो अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था** जिसके टार्गेट में अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा आता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया पर आफत की बरसात कर सकता है। इसके बाद प्योंगयांग ने चेताया कि वह अमेरिकी क्षेत्र गुआम की ओर मिसाइलों की झड़ी लगा सकता है।

क्या है

1. उत्तर कोरिया के आधिकारिक रेदोंग सिनमन अखबार के संपादकीय में कहा गया कि **संयुक्त सैन्य अभ्यास हमारे खिलाफ शत्रुता की बहुत ही मुखर अभिव्यक्ति है।** हमें इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि यह अभ्यास वास्तविक लड़ाई में नहीं बदलेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास आग में घी डालने के समान होगा और इससे प्रायद्वीप में हालात और बदतर होंगे।
2. संयुक्त सैन्याभ्यास **'उल्ची फ्रीडम गार्जियन'** में दस हजार से अधिक सैनिक शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास के बारे में कहा गया है कि यह खुद के बचाव के लिए है लेकिन परमाणु हथियार से लैस प्योंगयांग इसे उत्तर कोरिया के खिलाफ हमले की तरह देख रहा है।
3. प्योंगयाग द्वारा पिछले माह **दो इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण के बाद से प्रायद्वीप में तनाव के दौरान यह ड्रिल हो रहा है।**
4. दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि प्रायद्वीप में दो एयरक्राफ्ट करियर लाने की योजना को अमेरिका खत्म करने की सोच रहा था। यूएस पैसिफिक कमांड चीफ एडमिरल हैरी हैरिस रविवार को अभ्यास का मुआयना व उत्तर कोरियाई परमाणु व मिसाइल चेतावनियों पर विचार करने दक्षिण कोरिया गए।

एंटी डंपिंग फैसले पर चीन भडका

भारत ने चीनी मीडिया में छपी उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि **भारत ने चीन निर्मित 93 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की योजना बना रहा है।** इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक तौर पर गलत बताते हुए भारत ने स्पष्ट किया है कि **इन उत्पादों पर पहले से ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू है।** सरकारी मीडिया चाइना डेली में छपी रिपोर्ट के मुताबिक **भारत ने इस माह से चीन से आयातित 93 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है।**

क्या है

1. भारतीय दूतावास की ओर से यहां जारी एक बयान में स्पष्ट किया कि **भारत सरकार चीन में उत्पादित 93 सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की योजना बना रही है**, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है।
2. वर्तमान स्थिति यह है कि **चीन से केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और अन्य धातु के उत्पाद, फाइबर्स व यार्न, मशीनरी, रबर या प्लास्टिक के उत्पाद, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक्स आदि के 93 उत्पादों** पर पहले से ही एंटी डंपिग लागू है।
3. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि **भारत की ओर से व्यवसाय को गलत तरीके को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।** इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

4. मंत्रालय के अनुसार **भारत ने वर्ष 1994 के बाद चीन के 212 उत्पादों के खिलाफ जांच की है।** इसमें से **93 के खिलाफ अभी भी जांच जारी है।** इस साल अभी तक 13 उत्पादों की जांच शुरू की गई है। चाइना डेली के अनुसार अमेरिका के दबाव में भारत ने इस वर्ष चीनी उत्पादों के खिलाफ यह जांच शुरू की है।
5. **चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं** जो खुली बहुपक्षीय व्यवसायिक प्रक्रिया का समर्थन करता है। गाओ ने कहा कि दोनों देशों को चाहिए कि आपसी व्यापार को नुकसान पहुंचाने की बजाय विवाद के बिंदुओं पर आपस में वार्ता करें और आपसी सलाह मशविरा से इसका निपटारा करें जिससे दोनों के बीच व्यावसायिक सहयोग सुदृढ हो सकें और दोनों देश आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।

इंडियानापोलिस का मलबा मिला

द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में **जापानी पनडुब्बी के हमले का शिकार बने अमेरिकी युद्धपोत का मलबा 72 वर्ष बाद शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर में खोज निकाला है। यूएसएस इंडियानापोलिस** नामक इस युद्धपोत को जापानी शहर हिरोशिमा में गिराए जाने वाले परमाणु बम के कुछ हिस्सों को पहुंचाने के गोपनीय अभियान पर भेजा गया था।

क्या है

1. अभियान को अंजाम देकर लौटते वक्त **30 जुलाई, 1945 को एक जापानी पनडुब्बी ने इस पर हमला किया था।**
2. शोधकर्ताओं के इस दल का नेतृत्व कर रहे पॉल एलेन ने दावा किया है कि इंडियानापोलिस का मलबा प्रशांत महासागर में सतह से 18 हजार फीट (करीब 5.5 किलोमीटर) नीचे मिला है।
3. अमेरिकी नौसेना के इतिहास प्रभाग के अनुसार, **हमले के 12 मिनट बाद ही इंडियानापोलिस डूब गया था।** इस वजह से युद्धपोत से संकट संबंधी कोई संकेत नहीं भेजा जा सका था।
4. युद्धपोत पर सवार चालक दल के 1196 सदस्यों में से 800 ने समंदर में छलांग लगा दी थी। पांच दिन बाद इनमें से केवल 316 लोगों को ही बचाया जा सका था। बाकी लोग डिहाइड्रेशन या शार्क का शिकार बन गए थे। इंडियानापोलिस के चालक दल के 22 सदस्य अब भी जीवित हैं। अमेरिकी नौसेना उन्हें सम्मानित करने की योजना बना रही है।

अर्थशास्त्र

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2016-20** अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन से **केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीम-सम्पदा** (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंसकरण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना के पुन: नामकरण ''**प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना**'' का अनुमोदन कर दिया है।

क्या है

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना** का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
2. 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश के लैवरेज होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
3. पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा।
4. इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।
5. **इससे किसानों को बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी** और यह किसानों की आमदनी दोगुना करने के दिशा में एक बड़ा कदम है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

6. इससे रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे।
7. इससे कृषि उत्पादों की **बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्तआओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।**

पृष्ठभूमि

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना** के कार्यान्वयन से खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कार्यक्षम आपूर्ति प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
2. यह देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायक होगा और किसानों की आय को दुगुना करने का एक बड़ा कदम है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपाय

1. खाद्य प्रसंस्करण और सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार और निवेश में इसके योगदान के अनुरूप **भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभरा है।**
2. 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र का विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों में जीवीए का क्रमशः 9.1 और 8.6% हिस्सा था।
3. एनडीए सरकार के घोषणा पत्र का बल किसानों के लिए बेहतर आय उपलब्ध कराने तथा जॉब्स सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने को प्रोत्साहन देने पर है।

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य अनेक कदम उठाए हैं जैसे

1. **खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को गति देने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित** और अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार सहित व्यापार में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा तथा बैक एंड अवसंरचना का सृजन होगा और रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।
2. सरकार ने अभिहित खाद्य पार्कों और इनमें स्थित कृषि-प्रसंस्करण यूनिटों को रियायती ब्याज दर पर वहनीय क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए **नाबार्ड में 2000 करोड़ रूपए का विशेष कोष भी स्थापित किया है।**
3. **खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों** तथा शीतश्रृंखला अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) की परिधि में लाया गया है ताकि खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके और इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन मिलेगा, बर्बादी में कमी आएगी, रोजगार सृजित होगा एवं किसानों की आय बढ़ेगी।

डब्ल्यूटीओ में अमीर देशों के खिलाफ भारत और चीन

किसानों को अमीर देशों में कृषि उत्पादों पर मिल रही भारी भरकम सब्सिडी के खिलाफ **भारत और चीन ने संयुक्त मोर्चा खोल दिया है।** दोनों देशों ने **विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) इस तरह की सब्सिडी को खत्म करने की मांग** करने का प्रस्ताव रखा है। विकासशील देशों में किसानों को दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की अमीर देशों की नीति के खिलाफ मोर्चा लेते हुए भारत और चीन ने इसे **भेदभाव वाली नीति बताया है।**

क्या है

1. वाणिज्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि **भारत और चीन ने संयुक्त रूप से पिछले महीने डब्ल्यूटीओ में एक प्रस्ताव रखा है** जिसमें विकसित देशों में किसानों को मिल रही सब्सिडी को खत्म करने की मांग रखी है।
2. 18 जुलाई को दिये गए इस प्रस्ताव में कहा है कि **विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्य देश विकासशील देशों में गरीब किसानों को मिल रही सब्सिडी पर सवाल खड़े करते रहे हैं।** जबकि उनके अपने देशों में किसानों को **एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (एएमसी)** के नाम पर बड़ी मात्रा में कृषि सब्सिडी मिलती रही है।
3. भारत और चीन ने विश्व व्यापार में असंतुलन पैदा करने वाली विकसित देशों के कृषि सब्सिडी के प्रारूप को समाप्त करने की मांग की है। दोनों देशों की तरफ से डब्ल्यूटीओ में दिया गया यह संयुक्त प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि **दिसंबर में ब्यूनस आयर्स में होने वाली डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

है। इस बैठक में दोनों देश अन्य विकासशील देशों के समर्थन से इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। **डब्ल्यूटीओ में फैसला लेने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है जिसकी हर दो साल बाद बैठक होती है।**

4. संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि **अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और कनाडा जैसे विकसित देशों में किसानों को निरंतर भारी भरकम सब्सिडी दी जा रही है।** जबकि विकासशील देशों में किसानों को सब्सिडी के लिए काफी ऊंची सीमाएं डब्ल्यूटीओ ने निर्धारित कर रखी हैं। **ये देश सालाना 160 अरब डालर तक की राशि किसानों को सब्सिडी के तौर पर मुहैया करा रहे हैं।** जबकि भारत जैसे देश में सालाना एक किसान को 260 डालर की ही राशि सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध करायी जाती है। भारत और चीन जैसे अधिकांश विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ के तहत एएमसी की सुविधा नहीं दी गई है।
5. दोनों देशों के संयुक्त प्रस्ताव के मुताबिक कई विकसित देशों में तो उत्पाद की कुल लागत का 50 फीसदी और कई उत्पादों के मामले में तो 100 फीसद तक सब्सिडी के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। जबकि विकासशील देशों पर इसे 10 फीसद के दायरे में रखने की बाध्यता है।

सरकारी बैंकों के एकीकरण की रफ्तार हुई तेज

केंद्र सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुधार की सबसे बड़ी प्रक्रिया की गति और तेज कर दी है। **देश के 21 सरकारी बैंकों में विलय व अधिग्रहण की प्रक्रिया** को शुरु करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक **इन बैंकों की संख्या पहले चरण में घटा कर 10 से 12 की जाएगी।** लेकिन लंबी अवधि में इनकी संख्या और घटा कर 7 के करीब करने की होगी।

क्या है

1. सरकारी क्षेत्र में बैंकों के विलय को लेकर केंद्र सरकार पिछले डेढ़ दशक से विचार कर रही है। इस दौरान **कई समितियों का गठन किया गया** लेकिन कभी अमल नहीं किया जा सका।
2. **सबसे भारतीय बैंक संघ ने वर्ष 2003 में इसका रोडमैप तैयार किया था।** उसके बाद यूपीए सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव आर एस गुजराल की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने सभी बैंकों को मिला कर सात बड़े बैंक बनाने का सुझाव दिया था।
3. लेकिन तमाम वजहों से इन पर आगे नहीं बढ़ा जा सका। मौजूदा राजग सरकार ने एसबीआइ के साथ इसके पांच सब्सिडियरियों और एक अन्य भारतीय महिला बैंक के विलय की प्रक्रिया पूरी कर यह बता दिया था इस मुद्दे को अब ज्यादा दिनों तक नहीं लटकाया जाएगा।
4. **अगर ये बैंक फंसे कर्जे की समस्या से नहीं जूझ रहे होते विलय की प्रक्रिया को और तेजी से पूरी की जाती।** देश के सरकारी बैंक फिलहाल एक साथ कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो फंसे कर्जे यानी एनपीए (नान परफॉरमिंग एसेट्स) की दलदल में गले तक धंसे हुए हैं।
5. ताजे आंकड़ों के मुताबिक **कुल अग्रिम का 9.5 फीसद हिस्सा एनपीए में तब्दील हो चुका है।** देश के बैंकिंग इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। बड़े कर्जदारों से कर्ज वसूलने की नई प्रक्रिया शुरु की गई है।
6. दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये सारे बैंक भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में सरकार की तरफ से इन्हें 60 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है।
7. विलय के बाद एक बड़ा फायदा यह होगा कि देश के बड़े परियोजनाओं को ये बैंक अब ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलावों का ये बैंक ज्यादा आसानी से सहन कर सकेंगे।

क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) के आरक्षण के लिए **क्रीमीलेयर की आय सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रतिवर्ष** करते हुए केंद्रीय ओबीसी सूची में जातियों के उप वर्गीकरण के वास्ते एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली बताया कि केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों का उप वर्गीकरण करने के लिए आयोग बनाने की सिफारिश संविधान के **अनुच्छेद 340** के अंतर्गत राष्ट्रपति से की जाएगी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

क्या है

1. **यह आयोग अपने गठन की तिथि से 12 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगा।** आयोग केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल **पांच हजार से ज्यादा जातियों** का उप वर्गीकरण करेगा।
2. बैठक में ओबीसी आरक्षण लाभ लेने के लिए **क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने की** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सिफारिश स्वीकार कर ली गयी।
3. इस आयोग का नाम **'अन्य पिछड़ा वर्ग उप वर्गीकरण जांच आयोग' होगा।** यह आयोग केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जांच करेगा और इस असमानता को दूर करने के तौर-तरीके और प्रक्रिया तय करेगा।
4. **ओबीसी सूची में शामिल जातियों के उप वर्गीकरण की सिफारिश राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने 2011 में की थी।** इससे पहले 1992 में उच्चतम न्यायालय भी इस संबंध में व्यवस्था दे चुका है।
5. वर्ष 2012, 2013 और 2014 में संसदीय समितियों ने भी सूची में उप वर्गीकरण करने की सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि इन सिफारिशों के आधार पर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुड्डुचेरी, कनार्टक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तथा जम्मू-कश्मीर अपनी राज्य ओबीसी सूची का उप वर्गीकरण कर चुके हैं।
6. इस उप वर्गीकरण से उन जातियों को भी लाभ मिल सकेगा जो **अभी तक आरक्षण के लाभ से वंचित रही है।**
7. यह आयोग केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जांच करेगा, इस असमानता को दूर करने के तौर-तरीके, मानक और प्रक्रिया तय करेगा तथा पिछड़ा वर्ग के तहत मौजूद उप-वर्गों की पहचान करेगा।'

पर्वतीय राज्यों के उद्योगों को जीएसटी से राहत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **उत्तराखंड समेत 11 पर्वतीय राज्यों** के उद्योगों को जीएसटी से राहत देने के लिए 27413 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि **एक जुलाई** से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक कर छूट मिलती रहेंगी। हालांकि उन्हें यह छूट नई व्यवस्था में अब रिफंड के रूप में मिलेगी।

क्या है

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि **माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून** के मसौदे के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग निश्चित **समयावधि (31 मार्च 2027)** में अपने खुद की रिफंड व्यवस्था के हकदार होंगे।
2. पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में पूर्व उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत उद्योग को 10 साल की छूट मिलेगी।
3. **योजना के तहत इस अवधि के दौरान कामकाज शुरू करने वाले उद्योग को 10 साल के लिये उत्पाद शुल्क अवकाश मिलेगा।** साथ ही प्रत्येक उद्योग के लिये अलग से बची हुई अवधि होगी।
4. इसके तहत उत्पादन शुरू करने के बाद उन्हें **10 साल की छूट मिलेगी।** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत छूट के लिये कोई प्रावधान नहीं है लेकिन कानून के तहत एक प्रावधान है जो रिफंड की अनुमति देता है।
5. इस छूट के समाप्त होने का उपबंध बढ़ाकर 2027 कर दिया गया हैं इससे 4,284 औद्योगिक प्रतिष्ठान इस लाभ के हकदार होंगे। इसके लिये 27,413 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कारोबारी सुगमता पर सर्वे

सरकार व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाने का दावा भले ही करती हो लेकिन हकीकत यह है कि **देश में नया कारोबार शुरू करने में कम से कम 118 दिन लगते हैं।** यह अहम खुलासा **नीति आयोग की ओर से कराए गए एक सर्वे में हुआ है।** सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और वाणिज्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री निर्मला

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

सीतारमण ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक की। **'ईज ऑफ डूइंगः एन एंटरप्राइजेज सर्वे ऑफ इंडियन स्टेट्स' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट** के ये नतीजे इसलिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि **अब तक विश्व बैंक की सालाना 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट** में यह बताया जाता रहा है कि भारत में कारोबार शुरू करने में **मात्र 26 दिन लगते हैं।** हालांकि विश्व बैंक **यह रिपोर्ट सिर्फ दो शहरों- दिल्ली और मुंबई के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है** जबकि नीति आयोग ने आइडीएफसी इंस्ट्टियूट के साथ मिलकर यह सर्वे परे देश में किया है। हालांकि इस सर्वे में **अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है। सर्वे में छोटी-बड़ी 3,276 कंपनियों से सवाल पूछे गये।** इस सर्वे में **मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की 23 श्रेणियों को कवर किया गया है। यह पहला ऐसा सर्वे है जिसमें सरकार की ओर अब तक ईज ऑफ डूइंग के लिए हुए उपायों के जमीनी प्रभाव को दर्शाया गया है।**

रिपोर्ट के अनुसार

1. **बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे कम समय 63 दिन तमिलनाडु में लगते हैं** जबकि **आंध्र प्रदेश में इसमें 67 दिन का वक्त लगता है।** दूसरी ओर **केरल में व्यवसाय शुरू करने में 214 दिन** तथा **असम में 248 दिन लगते हैं।** रिपोर्ट में हालांकि यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अन्य राज्यों में बिजनेस शुरू करने में कितना वक्त लगता है।
2. **कंपनियों को जमीन अधिग्रहण में औसतन 156 दिन लगते हैं।** भूमि अधिग्रहण में सबसे कम समय हिमाचल प्रदेश में लगता है जहां यह काम 28 दिन में होता है जबकि पंजाब में 242 दिन और छत्तीसगढ़ में 213 दिन का समय लगता है।
3. **इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट पाने में औसतन 112 दिन का समय लगता है।** विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट-2017 में कहा गया था कि **भारत में कंस्ट्रक्शन परमिट पाने में 190 दिन लगते हैं।**
4. **इसमें भारत की रैंक 187 देशों में से 185वें नंबर पर थी।** आयोग की इस रिपोर्ट में दलील दी है गयी है कि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कंस्ट्रक्शन परमिट के संबंध में वास्तविक स्थिति नहीं दिखायी गयी।
5. कंस्ट्रक्शन परमिट मिलने के मामले में राज्यवार स्थिति का सवाल है तो **मध्य प्रदेश में यह 41 दिनों में मिल जाता है जबकि असम में इसके लिए 270 दिन और केरल में 117 दिन इंतजार करना पड़ता है।**
6. कंस्ट्रक्शन परमिट और अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत को अपनी विकास दर दहाई के अंक में ले जानी है तो व्यावसायिक माहौल सुधारना होगा।
7. रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि **भारत में बड़ी कंपनियों को जरूरी मंजूरी लेने में अधिक समय लगता है** जबकि छोटी कंपनियों को कम समय लगता है।
8. मसलन 100 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों को आवश्यक अनुमति लेने में अधिक समय लगता है जबकि 10 से कम लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों को कम।
9. इसके अलावा कारोबार करने में नियामक रुकावटों की शिकायतें भी बड़ी कंपनियों की ओर से अधिक आती हैं।

कुल NPA का 27 फीसद हिस्सा SBI का

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक और देश के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को अकेले सरकारी बैंकों के कुल एनपीए का 27 फीसद हिस्सा विलफुल डिफॉल्टर्स से वसूलना है।** आंकड़ों के मुताबिक एसबीआई को **विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले)** घोषित 1,762 कर्जदारों से 25,104 करोड़ रुपये वसूलने हैं। इन लोगों ने एसबीआई की बैलेंस सीट पर दबाव डाला है। ये आंकड़े इस साल 31 मार्च तक के हैं।

क्या है

क्या होता है एनपीए?

1. एनपीए यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का मतलब फंसे कर्ज से है जिससे बैंक को अब कोई आय नहीं हो रही है।
2. दरअसल जब **बैंक के किसी लोन खाते में 90 दिन तक ब्याज या मूलधन की किश्त का भुगतान नहीं होता है तो उसे एनपीए करार दे दिया जाता है।**
3. हालांकि फसली ऋण के मामले में यह सीमा दो फसलों की अवधि के बराबर है। अगर फसल दीर्घावधि की है तो यह सीमा एक फसल अवधि के बराबर है।

1. **अगला नंबर पीएनबी का:** कर्जदारों से बकाया वसूलने की जद्दोजहद में लगे सरकारी बैंकों में **एसबीआई के बाद दूसरा नंबर पीएनबी का आता है।**
2. पीएनबी के 1,120 घोषित डिफॉल्टर्स के पास बैंक का 12,278 करोड़ रुपये फंसा है। इस तरह ऐसे बकाएदारों के पास सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज का 40 फीसद यानी 37,382 करोड़ रुपये इन्हीं दोनों बैंकों के हिस्से का है।
3. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था। जबकि बीते वित्त वर्ष 2015-16 के अंत तक यह आंकड़ा 76,685 करोड़ रुपये का था।

रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने निम्नलिखित के **रणनीतिक विनिवेश से संबंधित निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:**

1. **वैकल्पिक व्यवस्था (एएम) की स्थापना करना** जिसमें **वित्त मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री एवं प्रशासकीय विभाग मंत्री शामिल होंगे** और जिस पर **अभिरुचि पत्र (ईओआई)** आमंत्रित करने के चरण से लेकर वित्तीय बोली आमंत्रित करने तक बिक्री के नियमों एवं शर्तों से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी होगी।
2. **प्रक्रियागत मुद्दों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने** और **सीसीईए के निर्णयों पर कारगर ढंग से अमल** के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करने हेतु सचिवों के मुख्य समूह (सीजीडी) को सशक्त करना।
3. इस मंजूरी से रणनीतिक विनिवेश से संबंधित सौदों को शीघ्र पूरा करने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप्स को सौ फीसद विदेशी पूंजी की मंजूरी

सरकार ने पहली बार स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति में स्थान देते हुए सौ फीसद फंडिंग विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों (एफवीसीआइ) से जुटाने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि स्टार्टअप के रूप में देश में नया व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को धनराशि जुटाने में आसानी होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जारी समेकित नीति के अनुसार** स्टार्टअप्स एफवीसीआइ से प्राप्त धनराशि के एवज में उन्हें **हिस्सेदारी, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकेंगे।**

क्या है

1. इसके अलावा **स्टार्टअप्स भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को कन्वर्टिबल नोट्स भी जारी कर सकेंगे।** पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को किसी भी भारतीय स्टार्टअप कंपनी से कन्वर्टिबल नोट्स खरीदने की अनुमति होगी। इस संबंध में कुछ शर्तें भी लागू होंगी।
2. **एफवीसीआइ एक बार में 25 लाख रुपये के कन्वर्टिबल नोट्स ही खरीद सकेंगे।** यह सुविधा एनआरआइ को भी मिलेगी। मंत्रालय ने इस दस्तावेज में हाल के वर्षों में एफडीआइ के संबंध में किए गए सभी नीतिगत बदलावों को शामिल किया है।
3. इस दस्तावेज में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में एफडीआइ को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है उनमें अनिवासी निवेशकों को कन्वर्टिबल नोट्स जारी करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होगी।
4. **स्टार्टअप्स को इस तरह के कन्वर्टिबल नोट्स जारी करने से पहले आरबीआई के नियमानुसार रिपोर्ट देनी होगी।** बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार नौकरियां सृजित करने के लिए स्टार्टअप कंपनियों पर फोकस कर रही है।
5. सरकार ने बीते एक साल में रक्षा, नागर विमानन व कंस्ट्रक्शन सहित दर्जन भर क्षेत्रों के संबंध में एफडीआइ नीति को उदार बनाया है।

देश का सबसे बड़ा एफडीआई सौदा

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

रुईया बंधुओं के एस्सार ऑयल ने अपने भारतीय कारोबार को रूसी कंपनी रोसनेफ्ट को 12.9 अरब डॉलर (करीब 83 हजार करोड़ रुपए) में बेचने के लिए बिक्री सौदा पूरा कर लिया है। इस सौदे की शुरुआत पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में हुई थी गौरतलब है कि **इस बड़ी डील का एलान बीते साल गोवा में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 15 अक्टूबर को किया गया था।**

क्या है

1. **घोषणा के ठीक 10 महीने बाद इस डील को अंतिम रूप दिया गया है।** यह देरी एस्सार आयल को कर्ज देने वाले बैंकों ने कंपनी पर अपने 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक के बकाया चुकाने की मांग की थी। इसे ही देरी की प्रमुख वजह बताया जा रहा है।
2. **एस्सार ऑयल लिमिटेड भारत में निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है।** इसे अब रूस की कंपनी रोजनेफ्ट ने खरीद लिया है। इस सौदे को रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश एवं **भारत में आनेवाला अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) माना जा रहा है।**
3. इस सौदे में रूसी कंपनी के नेतृत्व वाले संघ, जिनमें तेल बिडको भी शामिल है और ट्राफिगुरा-यूसीपी के नेतृत्व में एक निधि शामिल हैं। सौदे में गुजरात में वाडिनार में 20 मिलियन टन की रिफाइनरी की बिक्री, एक कैप्टिव पावर प्लांट, कैप्टिव बंदरगाह और 3,500 से अधिक पेट्रोल पंप शामिल है।
4. कंपनी के निदेशक प्रशांत रुईया ने बताया कि फर्म अपने कर्जदाताओं को जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक और स्टैंडर्ड चार्टेड समेत अन्य बैंक शामिल हैं को 70,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगा। इससे कंपनी पर कर्ज का बोझ 60 फीसद से अधिक घट जाएगा।

विज्ञान एवं तकनीकी

पानी को सस्ते में शुद्ध करेगा नैनो पार्टिकल

चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने के बाद अब नैनो पार्टिकल जल प्रदूषण को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसा **रिसाइक्लेबल नैनो पार्टिकल 'टिटेनियम फेराइट' विकसित किया है,** जिससे न सिर्फ किफायदी दर से पानी को साफ किया जा सकेगा, बल्कि उद्योगों से निकलने वाले **प्रदूषण जल, नदी, नालों, पोखरों, तालाबों के जल को भी शोधित किया जा सकेगा।** प्रो केएन उत्तम के मार्गदर्शन में हुए इस शोध को स्प्रिंगर पब्लिकेशन के जर्नल ऑफ मैटीरियल साइंस ने प्रकाशित किया है। खास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के बाजार में आने के बाद पानी साफ करने की लागत कई गुना कम हो जाएगी।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

क्या है

1. हमारे पूर्वजों ने पानी शोधित करने के लिए **धातु आधारित तकनीक विकसित कर रखी थी।** कहा जाता है कि यदि तांबे के पात्र में रातभर पानी भरकर रख दो तो सुबह तक पानी के अंदर के सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। **बढ़ते औद्योगीकरण और प्रदूषण के कारण अब यह तकनीक अप्रभावी हो चुकी है।**
2. बैक्टीरिया तो काफी हद तक मर जाते हैं पर पानी के अंदर टेक्सटाइल,चमड़ा व दवा जैसे उद्योगों से निकलने वाले कचरे को शोधित नहीं किया जा सकता।
3. **यदि औद्योगिक अपशिष्ट के कारण पानी का रंग नीला या काला पड़ गया हो** तो उसे शोधित करने की अभी दुनिया में कोई भी तकनीक सर्वसुलभ नहीं है।
4. यहां तक कि पानी को 100 प्रतिशत शोधित करने का दावा करने वाले वाटर प्यूरीफायर भी औद्योगिक कचरे के कारण प्रदूषित पानी को शोधित करने की सस्ती सुलभ तकनीक नहीं विकसित कर पाए हैं।
5. इस दिशा में **इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई यह तकनीकी कारगर उपाय साबित हो सकती है।**

कैसे साफ होता है पानी

1. **टिटेनियम डाईआक्साइड व आयरन डाईआक्साइड को मिलाकर टेबलेट फार्म में बुलेट (गोली) बनाई जाती है।**
2. इस को **'नियोडिमियम याग'** लेजर से पानी में लगभग एक घंटे तक वाष्पित किया जाता है। बुलेट को वाष्पित कर पानी में मिश्रित किया जाता है। इसके बाद मिश्रित पानी को वाष्पित किया जाता है।
3. इससे **नैनो पार्टिकल टिटेनियम फेराइट तैयार होता है।** भौतिक विज्ञानी प्रो. के.एन. उत्तम व आर. गोपाल ने बताया कि इस नैनो पार्टिकल की खासियत यह है कि यह रिसाइक्लेबल है।
4. प्रकाश और पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में **फोटो कैटलिसिस (प्रकाशीय उत्प्रेरक) प्रक्रिया से नैनो पार्टिकल जितना खर्च होता है उतनी मात्रा में फिर बन जाता है।** अभी तक पानी शोधित करने के जितने भी आरओ हैं उनमें नैनो पार्टिकल की लाइफ छह माह से एक साल तक होती है।
5. इसके बाद सर्विस कराने में तीन से चार हजार रुपये खर्च होता है। टेक्नोलॉजी से विकसित वाटर प्यूरीफायर में यह खर्च बचेगा। नैनो पार्टिकल से पानी तो शुद्ध होगा ही, साथ ही यह पार्टिकल सालों साल तक खत्म नहीं होगा।

पहले पृथ्वी पर आने का रहस्य सुलझा

वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है कि **प्राणी सबसे पहले धरती पर कैसे आए थे।** यह इस ग्रह के लिए एक बेहद अहम क्षण था, जिसके बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता। **ऑस्ट्रेलियन नैशनल यूनिर्वसिटी के शोधकर्ताओं** ने मध्य ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन अवसादी चट्टानों का विश्लेषण किया और पता लगाया कि **प्राणियों का विकास 65 करोड़ साल पहले शैवाल के उदय के साथ शुरू हुआ।**

क्या है

1. एएनयू के असोसिएट प्रोफेसर जोशेन ब्रोक्स ने कहा, **'हमने इन चट्टानों को पीस कर चूर्ण बना दिया और प्राचीन जीवों के अणुओं को इसमें से निकाल लिया'**। उन्होंने कहा कि शैवाल के उदय ने पृथ्वी के इतिहास में सबसे गहन पारिस्थितिकी क्रांतियों को शुरू किया। इसके बिना इंसान और अन्य प्राणियों का अस्तित्व न होता।
2. नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए इस शोध का नेतृत्व करने वाले ब्रोक्स ने बताया, **'ये मॉलिक्यूल्स बताते हैं कि 65 करोड़ साल पहले धरती बहुत दिलचस्प हो गई थी'।** यह इकोसिस्टम की क्रांति थी, यह शैवाल का उदय था। उन्होंने कहा कि शैवाल का उदय पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़ी पारिस्थितिक क्रांतियों में से एक था जिनके बिना इंसान और बाकी जानवरों का वजूद नहीं होता।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

3. **समुद्र में पोषक तत्वों के उच्च स्तर और अनुकूल वैश्विक तापमान ने शैवाल बनने के लिए पृथ्वी पर संपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर दीं।** ब्रोक्स ने बताया, भोजन के तल पर इन बड़ी पोषक रचनाओं ने जटिल पारिस्थितिक तंत्रों को ऊर्जा प्रदान की जहां बड़े और जटिल जानवर, जिनमें शुरुआती इंसान भी शामिल थे, पनप सकते थे।
4. ब्रोक्स के सहयोगी ऐंबर जेरेट ने बताया, **इन चट्टानों में हमने आणविक जीवाश्म की खोज की है।** हमें जल्द ही पता चल गया कि हमने यह बड़ी खोज कर ली है कि पूरी धरती के ठंडे होने का इसकी जटिल और लंबी जिंदगी से सीधा संबंध है।

कृत्रिम दिल का निर्माण

शोधकर्ताओं ने **मकड़ी के रेशम से बने दिल के मांसपेशीय टिशू बनाए हैं।** इन टिशू का निर्माण यह जांच करने के लिए किया गया है कि **कृत्रिम रेशम प्रोटीन हृदय के टिशू के निर्माण के लिए उपयुक्त हो सकते है** या नहीं। **इस्केमिक बीमारियों- जैसे कार्डियक इन्फ्रेक्शन** से हृदय की मांसपेशीय कोशिकाओं की स्थायी हानि का कारण बनती है। इसकी वजह से दिल की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिसका दिल के कार्य पर असर पड़ता है।

क्या है

1. **जर्मनी के इरलगेन-नर्नबर्ग (एफएयू) स्थित फ्रेडरिक एलेक्जेंडर विश्वविद्यालय के शोधकताओं** के अनुसार, रेशम कृत्रिम दिल के टिशू बनाने में कारगर हो सकता है।
2. **रेशम की संरचना व यांत्रिक स्थिरता देने का कार्य फाइब्रोनिन प्रोटीन करता है।**
3. शोध का प्रकाशन पत्रिका एडवांस्ड फक्शनल मटेरियल्स में किया गया है। शोधकर्ताओं के दल ने **दिल के टिशू के निर्माण के लिए प्रयोगशाला में उत्पादित रेशम प्रोटीन ईएडीएफ4की उपयुक्तता की जांच की है।**

भारतीय ने खोजा सेप्सिस का अचूक इलाज

अमेरिका में भारतीय चाइल्ड स्पेशलिस्ट **डॉ. पिनाकी पाणिग्रही ने सेप्सिस का सस्ता इलाज खोजा है।** जिसके बाद वे अमेरिकी अखबारों में छाए हुए हैं। **सेप्सिस एक घातक संक्रमण की बीमारी है** जिससे हर साल दुनियाभर में 60,000 बच्चों की मौत हो जाती है। अमेरिकी मीडिया संगठन, नेश्नल पब्लिक रेडियो (एनपीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, पाणिग्रही पिछले **प्रोबायोटिक जीवाणु का पता लगाने के लिए पिछले 20 सालों से इस विषय पर शोध कर रहे थे** जो आम, अचार और अन्य सब्जियों में पाया जाता है और ये नवजात शिशुओं में इस समस्या का अचूक ईलाज बन सकता है।

क्या है

1. बीजेबी कॉलेज, भुवनेश्वर और एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, ब्रह्मपुर के पूर्व छात्र **पाणिग्रही वर्तमान में नेब्रास्का मेडिकल सेंटर कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ के बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं।**
2. डॉक्टर ने बताया कि एक बार इस संक्रमण से प्रभावित होने पर बच्चे अचानक से निष्क्रिय हो जाते हैं वे रोना और अन्य हरकत करना भी बंद कर देते हैं। यह काफी तेजी से फैलता है और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उनकी मौत हो जाती है।
3. शोध में यह भी कहा गया है कि **जिन बच्चों ने कुछ शर्करा के साथ एक सप्ताह के लिए सूक्ष्म जीवों को खाया था,** उनमें सेप्सिस के कारण होने वाली मौत में नाटकीय कमी आई थी। उनमें 40 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
4. इतना ही नहीं, प्रोबायोटिक ने फेफड़ों में शामिल अन्य कई प्रकार के संक्रमणों को भी रोकने में मदद की।

चांद का अंदरूनी हिस्सा है सूखा

वर्ष 1972 में अपोलो 16 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से इकट्ठी की गई एक पुरानी चट्टान का विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि **पृथ्वी के इस उपग्रह का अंदरूनी हिस्सा बहुत सूखा प्रतीत होता है।** चंद्रमा पर नमी का सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पानी और अन्य वाष्पशील तत्वों और यौगिकों की मात्रा चंद्रमा के इतिहास और इसके बनने के बारे में संकेत देती है।

क्या है

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

1. अमेरिका में यूनिवसर्टी ऑफ कैलिफॉर्निया सैन डिएगो के जेम्स डे ने कहा, यह एक बड़ा सवाल रहा है कि **चंद्रमा सूखा है या नमीयुक्त।**
2. यह मामूली सी बात लग सकती है लेकिन असल में यह अहम है। डे ने कहा कि नतीजे दिखाते हैं कि जब चंद्रमा बना, तब वह बहुत अधिक गर्म था।
3. शोधकर्ताओं का मानना है कि वह इतना अधिक गर्म रहा होगा कि **जल या चंद्रमा की स्थितियों के तहत कोई अन्य वाष्पशील तत्व या यौगिक बहुत पहले ही वाष्पित हो गए होंगे।**
4. यह निष्कर्ष शोधकर्ताओं ने वर्ष 1972 में अपोलो 16 अभियान के दौरान चंद्रमा की सतह से एकत्र की गई एक पुरानी चट्टान का विश्लेषण कर निकाला है।

मंगल पर ऑक्सिजन बनाने की योजना

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (नैशनल एरनॉटिक्स स्पेस ऐडिमिनिस्ट्रेशन) मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सिजन बनाने की योजना बना रहा है। इसके लिए **साल 2020 में रोवर नाम के मिशन** के तहत वैज्ञानिक मंगल पर सूक्ष्मजीव भेजेंगे। **उसका इरादा साल 2020 में मंगल पर अपना अगला रोबॉट उतारने का है।** शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि मंगल पर कुछ खाने के बाद सूक्ष्मजीव ऑक्सिजन निकालेंगे। अगर यह प्रयोग कामयाब होता है तो भविष्य में मंगल पर इंसानों के बसने की कल्पना को सच करने की कोशिशों की तरफ यह बड़ा कदम होगा।

क्या है

1. इस समय **मंगल पर ऑक्सिजन की मात्रा केवल 0.13 प्रतिशत है,** जबकि **कार्बन डाइऑक्साइड 95 प्रतिशत है।** इसके अलावा **नाइट्रोजन और आरगॉन भी निम्न मात्रा में मौजदू हैं।**
2. इसकी तुलना में पृथ्वी के वातावरण में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन और 21 प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है। साथ ही अन्य मूलतत्व भी यहां मिलते हैं।
3. नासा के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक रॉबर्ट लाइटफूट ने बताया, **'मार्स 2020 मिशन के तहत एक प्रयोग जरिए हम मंगल पर ऑक्सिजन जनरेट करने की कोशिश करने जा रहे है'।**
4. नासा की योजना मार्स के आसपास एक चुंबकीय ढाल और एक न्यूक्लियर रिऐक्टर बनाने की भी है।

ऑनलाइन एफआइआर का सपना हुआ साकार

कंप्यूटर पर एक क्लिक के सहारे अपराधियों की सारी करतूतों का सच सामने आने का सपना काफी हद तक पूरा हो गया है। यही नहीं, अब एफआइआर के लिए थाने का चक्कर लगाने की झंझट भी नहीं रहेगी और आनलाइन ही इसे दर्ज करा सकेगें। इन तमाम खूबियों से लैस **डिजिटल पुलिस पोर्टल का गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उद्घाटन किया।** राजनाथ सिंह ने इसे प्रधानमंत्री के **मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस** की दिशा में अहम कदम बताया है। **यह पोर्टल सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम) का हिस्सा है।**

क्या है

1. राजनाथ सिंह ने कहा कि **देश की सभी पुलिस, खुफिया और जांच एजेंसियों को डिजिटल पुलिस पोर्टल का उपयोग करने की सुविधा दे दी गई है।**
2. इस पोर्टल के सहारे वे **11 तरीके के डाटा और 46 तरह के रिपोर्ट को कंप्यूटर के एक क्लिक के सहारे हासिल कर सकेंगे।**
3. इससे अपराधियों के पुराने सारे अपराधों को आसानी से देखा जा सकेगा और पुलिस की जांच और अपराधी को सजा दिलाने में आसानी होगी।
4. सबसे बड़ी बात यह है **कि इसके माध्यम से आम आदमी अब अपनी शिकायत आनलाइन भी पुलिस में दर्ज कर सकेगा।** इसके साथ वह केस में जांच की प्रगति को भी आनलाइन ही देख सकेगा।
5. फिलहाल **इस पोर्टल से देश के 15398 थानों में से 13775 थानों को जोड़ा जा चुका है** और अगले साल 31 मार्च तक बाकी बचे थानों को इससे जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस को अब लिखित शिकायत का भी डिजिटल डाटा इस पोर्टल पर डालना होगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

6. **सीसीटीएनएस के अगले चरण में इसे देश के सभी निचली अदालतों और जेलों के आनलाइन पोर्टल से जोड़ने की है।** ताकि अपराधियों के खिलाफ केस से जुड़ी सारी जानकारी जेल अधिकारियों, जजों और पुलिस अधिकारियों को एक साथ मिल सके। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीसीटीएनएस के पूरी तरह से क्रियान्वित होने के बाद आम जनता को पुलिस के एनओसी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
7. पासपोर्ट से लेकर कई तरह की सुविधाओं के लिए आम जनता को पुलिस से एनओसी लाना पड़ता है। इसके चालू होने के बाद आसानी से आनलाइन ही एनओसी हासिल किया जा सकेगा।

मांबा रैनसमवेयर ने फिर दी दस्तक

पिछले वर्ष दुनिया भर के कंप्यूटरों पर खतरनाक **मांबा रैनसमवेयर वायरस** का हमला हुआ था, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा था। इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर फिर दस्तक दे दी है। इससे भारत सहित कई देशों में सनसनी फैल गई है।

क्या है

1. फिरौती मांगने वाले **इस कंप्यूटर प्रोग्राम के इस वर्ष फिर सक्रिय होने की पुष्टि कैस्परस्काई लैब और ट्रेंड माइक्रो जैसी साइबर सिक्योरिटी फर्मो ने भी कर दी है।**
2. इस रैनसमवायर वायरस के हमले से कितनी भारतीय फर्मे प्रभावित हुई है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
3. मांबा रैनसमवेयर की खासियत यह है कि इस वायरस के प्रभाव से आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। फिर कंप्यूटर को मुक्त करने के लिए फिरौती की रकम मांगी जाती है।
4. आपके कंप्यूटर की सभी फाइलों के साथ हार्ड डिस्क भी लॉक यानी एनक्रिप्ट हो जाती हैं।

विविध

ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर दुनिया में रहने लायक सबसे शानदार शहर है, जबकि **कराची और ढाका** इस लिहाज से सबसे खराब शहरों में शामिल हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है। रिपोर्ट के अनुसार, रहने लायक सबसे शानदार शहरों में **मेलबर्न के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दूसरे स्थान पर** तथा **कनाडा का वैंकूवर तीसरे स्थान पर रहा है।** अन्य शीर्ष शहरों में चौथे से दसवें स्थान पर क्रमशः कैलगरी, एडीलेड, पर्थ, ऑकलैंड, हेल्सिंकी और हैमबर्ग काबिज हैं।

क्या है

1. **विश्व के 140 शहरों के इस सर्वेक्षण में पहले पांच पायदान के शहर पिछली रिपोर्ट से अपरिवर्तित हैं।** भारत का कोई भी शहर शीर्ष 10 शहरों में जगह पाने में नाकामयाब रहा है।
2. **10 निचले शहरों में भी भारत का कोई शहर नहीं है।** सीरिया का दमास्कस रहने के हिसाब से दुनिया का सबसे खराब शहर माना गया है। अन्य खराब शहरों में 139वें स्थान पर लागोस, 138वें स्थान पर त्रिपोली, 137वें स्थान पर ढाका, 136वें स्थान पर पोर्ट मोरेस्बी, 135वें स्थान पर अल्जीयर्स, 134वें स्थान पर कराची, 133वें स्थान पर हरारे, 132वें स्थान पर दोउआला और 131वेंस्थान पर कीव हैं।
3. **औसत वैश्विक जीवन संभाव्यता में भी हालिया वर्षों में गिरावट आयी है।** पिछले पांच साल में यह औसत 0.8 फीसदी गिरकर 7.48 फीसदी रह गया है।
4. रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच सालों में विश्व भर में अस्थिरता बढ़ी है तथा कई शहरों में उथल पुथल देखने को मिला है। आतंकवादी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
5. **फ्रांस और ब्रिटेन में लगातार हमले हुए हैं।** इन सब कारणों से इन क्षेत्रों के शहरों का स्थान नीचे आया है। इराक, लीबिया, सीरिया और तुर्की सैन्य संघर्षो तथा आम टकराव से जूझ रहे हैं।
6. नाईजीरिया जैसे कई देश भी आतंकवादी संगठनों से लगातार लड़ रहे हैं। अमेरिका जैसे स्थिर देश में भी ट्रंप की नीतियों तथा ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के कारण अशांति के हालात पैदा हुए हैं।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

सेना को मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर

केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के लिए 4168 करोड़ रुपये की लागत से **छह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर** खरीदने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। **यह हेलीकॉप्टर एक मिनट में 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर निशाना साधने में सक्षम है।** रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई। **सेना को पहली बार ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिलेंगे।** भारत ने 2015 में भी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक भारी हेलीकॉप्टरों की खरीद का तीन अरब डॉलर में सौदा किया था। बोइंग इन हेलीकॉप्टरों और उसके उपकरणों का निर्माण करती है।

अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में

1. **अपाचे को अमेरिकी सेना के एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था।** उस समय अमेरिकी सेना एएच-1 कोबरा हेलीकॉप्टर को प्रयोग करती थी। अपाचे ने पहली उड़ान 30 सितंबर 1975 को भरी थी।
2. **अपाचे को 1981 तक एएच-64 नाम से जाना जाता था।** इसे 1981 के अंत में अपाचे नाम दिया गया। अमेरिकी सेना में उस समय अपने हेलीकॉप्टरों का नाम अमेरिकी भारतीय जनजातीय नामों पर रखती थी। अप्रैल 1986 में अपाचे को अमेरिकी सेना में शामिल किया गया।
3. **आज ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के अलावा इजरायली वायुसेना, इजिप्टियन वायुसेना और नीदरलैंड की आर्मी इस्तेमाल करती है।** इजरायल इसी हेलीकॉप्टर की मदद से गजा पट्टी में अपने दुश्मनों पर कहर ढाती रही है। इस हेलीकॉप्टर में 30 एमएम गन लगी हुई है, जो बहुत ही घातक होता है।
4. **अपाचे में फिट सेंसर की मदद से यह अपने दुश्मनों को आसानी से तलाश कर उन्हें खत्म कर सकता है।** साथ ही इसमें नाइट विजन सिस्टम भी इंस्टॉल हैं। इसमें 30 मिलिमीटर की एक एम 230 चेन गन को मेन लैंडिंग गियर के बीच इंस्टॉल किया गया है और यह हेलीकॉप्टर की स्ट्राइकिंग कैपेसिटी को दोगुना करती है।
5. **अपाचे हेलीकॉप्टर में एजीएम-114 हेलीफायर मिसाइल लगे हैं,** तो हाइड्रा 70 रॉकेट पॉड्स भी लगे हैं। अमेरिका ने इन हेलीकॉप्टरों का इराक और अफगानिस्तान में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।
6. **ये हेलीकॉप्टर 293 किमी प्रतिघंटे की हिसाब से उड़ सकता है।** अपाचे की पूरी लंबाई 18 मीटर है, जिसमें दो पंख लगे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में टर्बोसाफ्ट इंजन लगे हैं। इसका वजन 5,165 किलो है। जिसमें 2 सीटें हैं।
7. **अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह वॉर जोन में लड़ाई के समय जरा भी फेल न हो।** अपाचे दुनिया के उन चुनिंदा हेलीकॉप्टर में शामिल है जो किसी भी मौसम या किसी भी स्थिति में दुश्मन पर हमला कर सकता है।

मानव तस्करी पर रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मानव तस्करी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2016 में सबसे ज्यादा मानव तस्करी वाले मामले पश्चिम बंगाल में हुए हैं। **इस लिस्ट में राजस्थान दूसरे नंबर पर हैं।** जून 2017 तक पश्चिम बंगाल में कुल 331 मामले सामने आए हैं।

एनसीबी के आंकड़ों के मुताबिक

1. **पिछले साल देश में मानव तस्करी के 8,132 मामले सामने आए, जिसमें से 3,576 मामले केवल पश्चिम बंगाल के हैं।**
2. राजस्थान में कुल 1,422 मामले सामने आए। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।
3. पश्चिम बंगाल के 24 परगना, नदिया, और मिदनापुर जिले की लड़कियों की तस्करी सबसे ज्यादा हुई है।
4. **इस तस्करी का मुख्य रास्ता बंगाल-नेपाल और बंगाल-बांग्लादेश का बॉर्डर है।**
5. मानव तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

सबसे कम उम्र के PM की वर्षगांठ

अक्टूबर, 1984 से दिसंबर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त, 1944 को हुआ था। आज (20 अगस्त) उनकी **73वीं वर्षगांठ है।** जब देश आजाद हुआ था तब राजीव गांधी सिर्फ 3 साल के थे

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

और आजादी के 37 सालों बाद 40 की उम्र में वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। देश के इतिहास में अब तक इतनी ज्यादा सीटों के साथ कभी सरकार नहीं बनी है और भविष्य में भी ऐसा दोबारा होने की उम्मीद नहीं **है। राजीव गांधी के शासनकाल में 508सीटों में से 401 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा था।**

उनके बारे में कुछ बाते

1. **आजाद भारत के इतिहास के सबसे कम 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने**
2. राजीव गांधी एक **फ्लाइंग क्लब के मैंबर भी थे** जहां से उन्होंने सिविल एविएशन की ट्रेनिंग भी ली थी।
3. 1970 में उन्होंने एक पायलट के तौर पर एयर इंडिया ज्वाइन किया था और 1980 तक पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले तक वो एयर इंडिया के लिए काम करते रहे।
4. नरेंद्र मोदी सरकार की ही तरह राजीव गांधी सरकार के दौरान भी देशभर में **डिजीटाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन** पर विशेष ध्यान दिया गया था।
5. **1981 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था।**
6. राजीव गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी ने 408 सीटों के बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई थी।
7. भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके कदमों की वजह से उन्हें मिस्टर क्लीन का भी दर्जा दिया गया था।
8. देश में बिजली, तकनीक और कंप्यूटर सेवा बहाल करने पर उनका हमेशा से जोर था और आज देश में अगर इतनी तेजी से कंप्यूटर तकनीक बदली है तो इसमें राजीव गांधी का योगदान अमूल्य माना जाएगा।
9. 21 मई 1991 को राजीव गांधी विशाखापट्टनम से चुनावी अभियान को पूरा करने के बाद श्रीपेरुंबदूर में रुके जो कि मद्रास से 22 किलोमीटर दूर है। यहां पर वह अपनी कार से उतरकर उस जगह की ओर पैदल ही चल पड़े जहां से उन्हें भाषण देना था।
10. इसी इवेंट के दौरान एलटीटीई (श्रीलंका में अलगाववादी मूवमेंट चला रहा एक ग्रुप) ने उनकी हत्या कर दी थी।

एच-1 बी के आवेदकों में भारतीय शीर्ष पर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा संबंधी नियमों को सख्त किए जाने के बावजूद भारतीयों का उत्साह कम नहीं हुआ है। इस बार भी **आवेदकों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है।** खबर है कि मौजूदा अमेरिकी वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान करीब 2.47 लाख भारतीय एच-1बी वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं और **इस तरह आवेदकों के सबसे बड़े ग्रुप की सूची में शीर्ष पर बरकरार हैं।**

क्या है

1. एक अक्टूबर, 2016 और 30 जून, 2017 के बीच कुल **आवेदनों की संख्या 74 फीसदी से अधिक है।** अमेरिकी वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है। 2015-2016 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीयों ने तीन लाख आवेदन दायर किए थे।
2. **हालांकि चीनी एच 1-बी उम्मीदवारों की संख्या इसकी तुलना में बहुत कम है।** 30 जून तक उनके वीजा आवेदकों की संख्या 36,362 हैं, जो कि उनके पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है।
3. चीन की तरफ से 2015-16 के दौरान कुल 35,720 आवेदन दायर किए गए थे। वहीं 30 जून 2017 तक 3,551 आवेदन के साथ कनाडा तीसरे स्थान पर है।
4. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा के अनुसार, 30 जून तक एच-1बी वीजा के लिए 3.36 लाख आवेदन मिले, जिनमें से 1.9 7 लाख को स्वीकार कर लिया गया हैं। हालांकि कई आवेदन अभी भी लंबित हैं।

अमेरिका में सम्मानित होंगे तीन भारतवंशी

अमेरिका में तीन भारतवंशियों को उद्यमिता में उनकी उपलब्धियों और सामुदायिक सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान 26 सितंबर को इंडो-अमेरिका चौंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन(आईएसीसीजीएच) के सालाना कार्यक्रम में दिया जाएगा।

क्या है

1. आईएसीसीजीएच के इस कार्यक्रम में ह्यूस्टन के शीर्ष कारोबारी और निर्वाचित हस्तियां शामिल होती हैं। इस मौके पर **मैरी गोराडिया को इंपैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, स्वप्निल अग्रवाल को यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और**

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

बाल सरीन को इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जबकि अमेरिकी नागरिक जेनिस लोंगोरिया को इकोनॉमिक इंपैक्ट अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा।

2. पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा आईएसीसीजीएच के अध्यक्ष एलेन रिचर्ड ने की। उन्होंने कहा कि इनका चयन उद्यमिता और मानवीय सेवा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए किया गया है।
3. भारतवंशी सीईओ बॉब पटेल विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में ह्‌यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डॉ. अनुपम राय मुख्य अतिथि होंगे।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2017

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रति वर्ष खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्ष की अवधि में खिलाड़ी द्वारा शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, अर्जुन पुरस्कार लगातार चार वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के लिए कोचों को** और खेल विकास के क्षेत्र में जीवन भर योगदान देने के लिए **ध्यानचंद पुरस्कार** प्रदान किया जाता है।

क्या है

1. इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन प्राप्त हुए थे, जिन पर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोचों, ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों, खेल पत्रकारों/जानकारों/कमेंटेटरों और खेल प्रशासनिक अधिकारियों की चयन समिति ने विचार किया था।
2. **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार की चयन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.के. ठक्कर** (उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, हिमाचल और बाम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) थे। द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कारों की चयन समिति के अध्यक्ष श्री पुलेला गोपीचंद थे।

समिति की सिफारिशों के आधार पर और उचित जांच के बाद सरकार ने निम्नलिखित खिलाडियों/कोचों/संगठनों को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है:–

(i) राजीव गांधी खेल रत्न 2017

क्र.सं.	पुरस्कृत का नाम	खेल विधा
1.	श्री देवेन्द्र	पैरा एथलिट
2.	श्री सरदार सिंह	हॉकी

(ii) द्रोणाचार्य पुरस्कार 2017

क्र.सं.	पुरस्कृत का नाम	खेल विधा
1.	स्वर्गीय डॉ. आर. गांधी	एथलेटिक्स
2.	श्री हीरा नंद कटारिया	कबड्डी
3.	श्री जी.एस.एस.वी प्रसाद	बैडमिंटन (लाइफ टाइम)
4.	श्री ब्रिज भूषण मोहंती	बॉक्सिंग (लाइफ टाइम)
5.	श्री पी.ए. राफेल	हॉकी (लाइफ टाइम)
6.	श्री संजॉय चक्रवर्ती	निशानेबाजी (लाइफ टाइम)
7.	श्री रोशन लाल	कुश्ती (लाइफ टाइम)

(iii) अर्जुन पुरस्कार 2017

क्र.सं.	पुरस्कृत का नाम	खेल विधा
1.	सुश्री वी.जे. सुरेखा	तीरंदाजी
2.	सुश्री खुशबीर कौर	एथलेटिक्स

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

3.	श्री अरोकिया राजीव	एथलेटिक्स
4.	सुश्री प्रशांति सिंह	बास्केट बॉल
5.	सूबेदार लैशराम देबेन्द्रो सिंह	मुक्केबाजी
6.	श्री चेतेश्वर पुजारा	क्रिकेट
7.	सुश्री हरमनप्रीत कौर	क्रिकेट
8.	सुश्री ओइनम बेम्बम देवी	फुटबॉल
9.	श्री एस.एस.पी. चौरसिया	गोल्फ
10.	श्री एस.वी. सुनील	हॉकी
11.	श्री जसवीर सिंह	कबड्डी
12.	श्री पी.एन. प्रकाश	निशानेबाजी
13.	श्री ए. अमलराज	टेबल टेनिस
14.	श्री साकेतमिनेनी	टेनिस
15.	श्री सत्यवर्त कादियान	कुश्ती
16.	श्री मरियप्पन	पैरा-एथलिट
17.	श्री वरुण सिंह भाटी	पैरा-एथलिट

(iv) ध्यान चंद पुरस्कार

क्र.सं.	**नाम (श्री/सुश्री)**	**खेल विधा**
1 .	श्री भूपेन्द्र सिंह	एथलेटिक्स
2.	श्री सैयद शाहिद हकीम	फुटबॉल
3.	सुश्री सुमाराई टेटे	हॉकी

29 अगस्त, 2017 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कृत खिलाड़ियों और व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों को पदक और अलंकरण के अलावा 7.5-7.5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यान चंद पुरस्कार से सम्मानित प्रत्येक खिलाड़ी/व्यक्ति को प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5-5 लाख रुपये नकद पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

इंफोसिस के नए चेयरमैन

नंदन निलेकणी को इंफोसिस का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। विशाल सिक्का के इस्तीफे के बाद से ही कंपनी में चल रही स्थिरता को बहाल करने के प्रयास में बोर्ड में यह बड़ा बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि **सिक्का के इस्तीफे ने नारायण मूर्ति और बोर्ड के बीच कड़वाहट** को सामने ला दिया था। कंपनी ने यह जानकारी रेग्युलेटरी फाइलिंग में दी है। अपनी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि **आर शेषशाई ने बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है।**

कौन है निलेकणि

1. **नंदन निलेकणी इंफोसिस के को-फाउंडर रहे हैं।** साल 2002 से अप्रैल 2007 तक वो बतौर सीईओ अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
2. **साल 2009 में उन्होंने कंपनी को अलविदा कह दिया था।** उसके बाद वो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), आधार प्राधिकरण के मुखिया बने। निलेकणि ने इस भूमिका को साल 2014 तक बखूबी निभाया।
3. उन्होंने बेंगलुरू (दक्षिण) से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

21 से घटकर 12 रह जाएंगे सरकारी बैंक

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

विरासत में मिली लचर बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने की कोशिश केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार चल रही है। इस दिशा में कैबिनेट ने सरकारी बैंकों में विलय व एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार की मंशा यह है कि **तीन वर्षो में मौजूदा 21 बैंकों की संख्या घटाकर 10-12 कर दी जाए।** बाद में यह संख्या और घटेगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया, **'नई वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य देश में मजबूत व प्रतिस्पर्धी बैंकों को स्थापित करना है।** लेकिन विलय व एकीकरण का प्रस्ताव बैंकों की तरफ से ही आएगा। सरकार पूरी तरह से इन बैंकों के वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी। माना जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत **विभिन्न मंत्रालयों को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी।**

क्या है

1. **वित्त मंत्री जेटली इस समिति के अध्यक्ष होंगे।** यह समिति रिजर्व बैंक के सहयोग से बैंक विलय के प्रस्तावों का रोडमैप बनाएगी और बैंकों की तरफ से आने वाले प्रस्तावों को लागू करने में मदद करेगी। कुछ बैंकों में विलय की बात पहले से ही शुरू हो चुकी है।
2. **पिछले वर्ष भारतीय स्टेट बैंक में उसके पांच सहायक बैंक** व भारतीय महिला बैंक के विलय की सफलता के बाद सरकार का भरोसा बढ़ा है कि अब अन्य बैंकों में भी विलय व एकीकरण का काम बगैर किसी खास रुकावट के हो सकता है।
3. सरकार की तरफ से इस बात का भरोसा दिलाया गया है इस प्रक्रिया में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाए। अगर कोई समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेना चाहता है तो वह जरूर दिया जाएगा।
4. **सरकार की तरफ से भी कुछ बैंकों को विलय के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।** इस बारे में फैसला कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
5. **इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक के विलय की संभावना भी जताई जा रही है।** इस तरह से इन बैंकों की संख्या कम जरूर होगी लेकिन वित्तीय तौर पर ये ज्यादा मजबूत होंगे।
6. ज्यादा कर्ज दे सकेंगे और बाजार की अनिश्चितता या वैश्विक मंदी को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल सकेंगे। आकार बड़ा होने की वजह से इन बैंकों के लिए बाहर से फंड जुटाना आसान होगा। सरकार पर इनकी निर्भरता कम होगी।

लिंक्डइन पॉवर प्रोफाइल सूची 2017

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लिंक्डइन पॉवर प्रोफाइल सूची 2017 में बेहतर स्थान पाने वालों में शामिल है। पेशेवर नेटवर्किंग लिंक्डइन ने **अपने पॉवर प्रोफाइल का चौथा संस्करण जारी किया।** इंटरनेट के इस पेज पर यूजर अपने कैरियर, शिक्षा और अन्य बातों को साझा करते हैं। देश में पेशेवर लोगों के बीच लिंक्डइन बेहद लोकप्रिय है। **इस प्लेटफार्म पर मोदी के दो लाख 20 हजार फालोअर हैं।** प्रधानमंत्री तीसरी बार इस सूची में आए हैं।

क्या है

1. **सूची में नेटवर्क ने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने वाले 50 लोगों को रखा है।** सूची में शामिल लोगों ने अपनी सफलता को ब्रांड के रूप में स्थापित किया है।
2. मोदी और प्रियंका के अलावा **कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स** फाउंडेशन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सिप्ला के ग्लोबल चीफ पीपुल अफसर प्रबीर झा, सिओमी टक्नोलाजी के वाइस प्रेसिडेंट एवं प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन ने भी सूची में जगह पाई है।
3. **लिंक्डइन इंडिया के कंट्री मैनेजर एवं प्रोडक्ट हेड अक्षय कोठारी ने कहा कि 2017 के हमारे पॉवर प्रोफाल ने एक मजबूत ब्रांड तैयार किया है।** यह ब्रांड सदस्यों से संबंधित मुद्दों पर विचारों और विभिन्न अनुभवों को साझा करने से तैयार हुआ है।

खेल प्रतिभा खोज पोर्टल आरम्भ

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

युवा एवं खेल मंत्रालय ने देश के युवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश के लिए प्रतिभा खेल पोर्टल आरम्भ किया। इस पोर्टल को उपराष्ट्रपति **श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा इंदिरा गाँधी स्टेडियम,** नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आरम्भ किया गया। खेल क्षेत्र में इस महत्त्वपूर्ण पहल को देखने के लिए **युवा मामले और खेल राज्य मंत्री, (स्वतन्त्र प्रभार) श्री विजय गोयल,** सचिव, खेल श्री इंजेटी श्रीनिवास, खेल रत्न एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी तथा हजारों स्कूली छात्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे। स्कूली छात्रों ने इस अवसर पर **कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।** इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि **इस तरह की पहल से न केवल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को जानने में सहायता मिलेगी** अपितु सभी आवेदकों को एक स्तरीय खेल क्षेत्र प्राप्त होगा तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भी बनेगा।

क्या है

1. उन्होंने कहा कि **खेल राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है।** क्योंकि खेल **वैयक्तिक विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक सहभागिता और आर्थिक विकास** के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी देश को **खेल शक्ति बनने के लिए एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है सही प्रतिभा की पहचान करना और उसका विकास करना।**
2. विश्व में **कुल आबादी का सातवाँ हिस्सा हमारे देश में निवास करता है।** और यहां विशेष रूप से 450 मिलियन युवाओं में प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है। श्री नायडू ने कहा कि वास्तव में तो हमारे देश में अत्यधिक प्रतिभाएं मौजूद हैं परन्तु इन्हें उपयोग में लाने के लिए प्रतिभाओं को सहायता देने और आगे बढ़ाने एवं विश्व चौम्पियन बनने के लिए हमें प्रतिभाओं को पहचानने और उनमें वृद्धि करने हेतु एक व्यापक व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश

मुंबई के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ मध्य रात्रि में सुनवाई करने तथा निर्भया बलात्कार कांड के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखने वाले न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग वहां मौजूद थे।

क्या है

1. राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित **एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद न्यायमूर्ति मिश्रा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।**
2. उनका कार्यकाल तीन अक्टूबर 2018 को समाप्त होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश **जगदीश सिंह केहर** को सेवानिवृत्त हो गए।
3. **न्यायमूर्ति मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बनने वाले ओडिशा की तीसरे न्यायाधीश होंगे।** उनसे पहले ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा और न्यायमूर्ति जीबी पटनायक भी इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। न्यायमूर्ति मिश्रा याकूब मेमन पर दिए गए फैसले के कारण काफी सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने रात भर सुनवाई करते हुए याकूब की फांसी पर रोक लगाने संबंधी याचिका निरस्त कर दी थी।
4. वह पटना और दिल्ली उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। **तीन अक्टूबर 1953 को जन्मे न्यायमूर्ति मिश्रा को 17 फरवरी 1996 को उड़ीसा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया था।** तीन मार्च 1997 को उनका तबादला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कर दिया गया। उसी साल 19 दिसंबर को उन्हें स्थायी नियुक्ति दी गयी।
5. चार दिन बाद 23 दिसंबर 2009 को उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और 24 मई 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वहां रहते हुए उन्होंने पांच हजार से ज्यादा मामलों में फैसले सुनाये और लोक अदालतों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के प्रयास किये। उन्हें 10 अक्टूबर 2011 को पदोन्नत करके उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
6. न्यायमूर्ति मिश्रा ने ही देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के आदेश जारी किए थे।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

प्लास्टिक बैग केन्या में सबसे बड़ी सजा

अफ्रीकी देश केन्या ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर दुनिया में सबसे कड़े दंड का प्रावधान किया है। इन प्रावधानों के तहत, प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर चार साल की कैद या 40 हजार डॉलर (25 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्लास्टिक बैग से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए इस दंड व्यवस्था को लागू किया गया है। **प्लास्टिक बैग पर कड़ा प्रतिबंध लागू करके केन्या 40 से ज्यादा देशों के उस समूह में शामिल हो गया है** जो इस प्रदूषणकारी उत्पाद के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। **समूह में चीन, फ्रांस, इटली, रवांडा जैसे देश शामिल हैं।** केन्या में खाद्य पदार्थों को रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये बैग जहां-तहां फेंके जाते हैं। परिणामस्वरूप **समुद्र में पाई जाने वाले व्हेल, डॉल्फिन मछलियों, कछुओं, नदियों की मछलियों और सड़क पर घूमने वाले जानवरों के आमाशय और आंतों में प्लास्टिक बैग पाए गए हैं।** प्लास्टिक बैग ने समुद्री पर्यावरण पर खासा असर डाला है। भारत समेत कई देशों में प्लास्टिक बैग ने जल निकासी व्यवस्था और मिट्टी के गुणों को भी प्रभावित किया है।

क्या है

1. केन्या में **संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम से जुड़े हबीब अल-हैबर के अनुसार,** प्लास्टिक बैग को गलकर विलीन होने में **पांच सौ से एक हजार साल का समय लगता है।** तब तक यह खाद्य श्रृंखला में शामिल होकर इंसान और जानवरों में अपना प्रभाव छोड़ देगा। इसलिए समय रहते इसके खतरे को काबू करने की जरूरत है।
2. **केन्या क्षेत्र में प्लास्टिक बैग के बड़े निर्यातकों में से एक है।** वहीं, प्लास्टिक बैग निर्माताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे 60 हजार रोजगार पर असर पड़ेगा। केन्या ने बीते 10 साल में तीन कोशिश के बाद यह प्रावधान तय किया। गौरतलब है कि **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक, केन्याई सुपरमार्केट्स में हर साल करीब 10 करोड़ प्लास्टिक बैग दिए जाते हैं।** हालांकि इन्होंने विकल्प के तौर पर पहले ही कपड़े के बैग देना शुरू कर दिए हैं।

फ्लैशबैक

1. बांग्लादेश दुनिया का पहला देश है जिसने प्रतिबंध लगाया था। वहां 2002 में यह कानून लागू हुआ था।
2. मोरक्को, तंजानिया, मॉरिशियाना जैसे अफ्रीकी देशों में भी प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है। कनाडा के कुछ शहरों में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा है। मॉन्ट्रियल में 2018 तक पूर्ण रूप से बैन की तैयारी है। नाईजीरिया में प्रतिबंध नहीं, लेकिन यहां प्लास्टिक बैग से महिलाओं को पुनः उपयोग किए जाने वाले बैग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और तय कीमतों पर बेचा जाता है।

खेल दिवस

राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन **सन 1905 में ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था।** भारत के महान हॉकी खिलाड़ी **मेजर ध्यानचंद सिंह को दुनियाभर में हॉकी के बाजीगर के नाम से जाना जाता है,** जिन्होंने न सिर्फ भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया बल्कि हॉकी को एक नई ऊंचाई तक ले गए। **मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन् 1905 ई. को इलाहाबाद में हुआ था।**

ध्यानचंद जी की लाइफ से जुड़े 10 फैक्ट्स

1. **21 वर्ष की उम्र में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुन लिया गया।** इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते।
2. 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद 1928 के एम्सटर्डम ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। यहां चार मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए।
3. **ध्यानचंद के बारे में मशहूर है कि उन्होंने हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किए।**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

4. 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद और उनके बड़े भाई रूप सिंह ने आठ-आठ गोल ठोंके।
5. **1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे।** 15 अगस्त, 1936 को हुए फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया।
6. 1948 में 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहा।
7. हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद को जर्मन सेना में शामिल कर एक बड़ा पद देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया।
8. **वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है,** जिसमें उनको चार हाथों में चार स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है।
9. **1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।** उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है।
10. इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

संयुक्त राष्ट्र ने खोला यूरेनियम बैंक

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) ने कजाखिस्तान में निम्न संवर्धित यूरेनियम बैंक खोला है। इसका मकसद राजनीतिक या बाजार के चलते बाधा खड़ी होने पर परमाणु ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु ईंधन रिजर्व 29 अगस्त को खोला गया। **इसमें 90 टन निम्न संवर्धित यूरेनियम (एलईयू) का भंडारण किया जाएगा।**

क्या है

1. **यह लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टरों के लिए ईंधन बनाने की जरूरी सामग्री है।** ये रिएक्टर बिजली पैदा करते हैं। एलईयू आमतौर पर खुले बाजार या देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत खरीदा जाता है। यूरेनियम बैंक एलईयू की आपूर्ति को सुचारु रखने के उद्देश्य से खोला गया है।
2. यह भंडारण उन स्थितियों के लिए है जिसमें **संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य देश किसी वजह से परमाणु ईंधन हासिल नहीं कर सकता।**
3. **वैश्विक उपयोग के लिहाज से 90 टन का रिजर्व कम हो सकता है** लेकिन इससे किसी बड़े शहर के लिए तीन साल तक बिजली पैदा की जा सकती है।

बिटक्वॉइन को टक्कर देने उतरा बर्गर किंग

रेस्टोरेंट चेन बर्गर किंग ने रशिया में अपनी नई क्रिप्टोकरेंसी वूपरक्वॉइन की शुरूआत की है। बिटक्वॉइन की तर्ज पर शुरू की गई **इस वर्चुअल करेंसी का नाम बर्गर किंग रेस्टोरेंट चेन** ने अपने सबसे पॉपुलर सैंडविच वूपर से जोड़ा है। गौरतलब है कि **बिटक्वॉइन की खिलाफत करने वाले रशिया ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपने नियमों में कुछ रियायतों की घोषणा की है।** इससे पहले बिटक्वॉइन के ट्रेडर्स को जेल भेजने तक की बात भी चल रही थी। लेकिन रशिया के पहले उप प्रधानमंत्री इगोर शुवालोव खुलकर क्रिप्टोकरेंसी के समर्थन में आ गए हैं।

कैसे काम करेगी यह वर्चुअल करेंसी

1. **करीब 90 देशों में मौजूद यह रेस्टोरेंट चेन इस वर्चुअल करेंसी** का इस्तेमाल अपने ग्राहकों को रिवॉर्ड देने में करेगा। **वूपर सैंडविच को खरीदने वाले ग्राहक को डिजिटल वॉलेट में वूपर क्वॉइन ट्रांसफर किए जाएंगे।** ग्राहक इन क्वॉइन को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है या उनके बदले बर्गर खरीद सकता है। कंपनी धीरे-धीरे इस क्वाइन की कीमत में इजाफा भी होने का आश्वासन दे रही है।
2. **वूपरक्वॉइन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म** पर काम करेगा। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म यूजर्स को पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज पर ट्रांसफर और ट्रेड करने की सुविधा देता है। यह ट्रांजेक्शन लैजर पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। कंपनी **एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर** में भी अगले महीने एप लेकर आएगी ताकि कस्टमर वूपर क्वॉइन के टोकन खरीद सकें।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

3. गौरतलब है कि **क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दुनियाभर के देशों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।** बिटक्वॉइन ने हाल के समय में जो तेजी दिखाई है उसकी ग्रोथ को लेकर सभी हैरान हैं।
4. पिछले ही हफ्ते एस्टोनिया ने अपनी सरकार समर्थित क्रिप्टोकरेंसी एस्टक्वॉइन की शुरुआत की है।

ओबीसी आरक्षण की ढाई दशक पुरानी विसंगति दूर

ओबीसी के बीच पकड़ मजबूत करने में जुटी मोदी सरकार इस कोटे में विसंगतियों को दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के **उपक्रमों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में ओबीसी में क्रीमीलेयर की पहचान** में चली आ रही गड़बड़ी को दुरुस्त कर दिया है। इन संस्थानों में **सरकार के समकक्ष क्रीमीलेयर पदों की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण** उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चे भी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठा रहे थे। अब इन संस्थानों के भी **उन अधिकारियों के बच्चों को ओबीसी आरक्षण मिलेगा**, जिन्हें इसकी जरूरत है। पिछले हफ्ते ही **सरकार आरक्षण का लाभ ओबीसी के वंचित वर्गो तक पहुंचाने के लिए ओबीसी कोटे** के वर्गीकरण को हरी झंडी दे चुकी है।

क्या है

1. **24 साल पहले 1993 में जब ओबीसी के लिए आरक्षण** लागू करने के साथ ही अदालत के निर्देशानुसार **क्रीमीलेयर को इससे वंचित करने का आदेश जारी हुआ था।** लेकिन इसमें पीएसयू, सरकारी बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों में क्रीमीलेयर तय करने बजाय सिर्फ उसे केंद्र सरकार के समकक्ष पद कह कर छोड़ दिया गया था। समकक्ष पद की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में इन संस्थानों के बड़े-बड़े अधिकारी भी खुद को क्रीमीलेयर से बाहर दिखा देते थे और उनके बच्चे आरक्षण के हकदार बन जाते थे और जरूरतमंद लोग आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते थे।
2. कैबिनेट ने अब साफ कर दिया है कि **पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में किस-किस स्तर के अधिकारियों को क्रीमीलेयर के दायरे में माना जाएगा।**
3. इसके तहत **पीएसयू में बोर्ड के सदस्य से लेकर प्रबंधन से जुड़े सभी एक्जीक्यूटिव पद केंद्र सरकार के ए-श्रेणी के पद** के समान माने जाएंगे यानी उन्हें क्रीमीलेयर का माना जाएगा।
4. इसी तरह से **सार्वजनिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-एक** और इससे ऊपर के अधिकारियों को **केंद्र सरकार के ए-श्रेणी के अधिकारियों के समान माना जाएगा** और वे क्रीमीलेयर के दायरे में आएंगे।
5. **पीएसयू और सार्वजनिक बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं में निचले स्तर** के अधिकारियों को बच्चों को ओबीसी का लाभ तो मिलेगा, लेकिन सालाना आय वाली क्रीमीलेयर की सीमा उनपर भी लागू होगी। पिछले हफ्ते सरकार क्रीमीलेयर की सीमा को छह लाख सालाना आमदनी से बढ़ाकर आठ लाख रूपये कर चुकी है।
6. **ओबीसी कोटे में वर्गीकरण के लिए एक आयोग बनाने का फैसला लिया था।** इसे यह देखने को कहा गया है कि ओबीसी के अंदर केंद्रीय सूची में शामिल जातियों को उनकी संख्या के अनुरूप सही मात्रा में आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं।
7. वंचित जातियों को इसका लाभ कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ध्यान रहे कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने तीन वर्गो में वर्गीकरण का सुझाव दिया था। ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है। दूसरा वर्ग जो ज्यादा पिछड़ा है और तीसरा जो अतिपिछड़ा है। भावी आयोग उन जातियों की संख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा।

एलियंस के होने का मिला एक और सबूत

हाल ही में **एक भारतीय वैज्ञानिक ने 15 एफआरबी (फास्ट रेडियो बर्स्ट) का पता लगाया है।** पांच घंटे की निगरानी के बाद **ये एफआरबी एक छोटी आकाशगंगा में दिखाई दिए हैं।** जिस छोटी आकाशगंगा में इन एफआरबी का पता लगाया गया है, वह **पृथ्वी से तीन मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं।** यह खोज **ब्रेकथ्रू लिसन के शोधकर्ता और भारतीय वैज्ञानिक विशाल गज्जर ने की है।** बैकथ्रून लिसन प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए एक भारतीय वैज्ञानिक ने 15 फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) का पता लगाया है। यह **15 एफआरबी छोटी आकाशगंगा में डिटेक्ट किए गए हैं, जो कि धरती से करीब 3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है।** पांच घंटे की लंबी निगरानी के बाद वैज्ञानिक इन 15 एफआरएफ को डिटेक्ट करने में

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

कामयाब हुए। यह पहली बार है जब किसी **सोर्स के जरिए इस फ्रिक्वेंसी पर इन एफआरबी को देखा गया है।** अनुमान लगाया जा रहा है कि यह एफआरबी कहीं, **एलियन के होने का सबूत तो नहीं है।** इनके जरिए एलियन धरती की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हों। बता दें कि **बैकथ्रून लिसन प्रोग्राम 100 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम है,** जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ब्रह्मांड में इंटेलीजेंट लाइफ के चिह्न खोजने के लिए इसे लॉन्च किया गया था।

क्या है

1. अनुमान लगाया जा रहा है कि **यह एनर्जी सोर्स है, जो एक्स्ट्रा-टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा स्पेसक्राफ्ट में उपयोग किया जाता है।** कहा जा रहा है कि इन 15 फास्ट रेडियो बर्स्ट ने जब आकाशगंगा को छोड़ा था, तब हमारा **पूरा सोलर सिस्टम 2 बिलियन वर्ष का था।**
2. **एफआरबी की खोज पहली बार नवंबर 2012 में हुई थी।** साल 2015 में पहला एफआरबी देखा गया और 2016 में पहले एफआरबी की लोकेशन का पता लगाया गया।
3. **इंटरनेट इनवेस्टर और फिलेन्थ्रोफिस्ट यूरी मिलनर और स्टेफन हॉकिन्स द्वारा 2015 में लॉन्च की गई** वैश्विक खगोलीय पहल ब्रेकथ्रून लिसन के जरिए करीब आकाशगंगाओं और करीब के तारों की निगरानी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यूसी बर्कले की साइंस टीम ने एफआरबी को अपनी टारगेट लिस्ट में शामिल किया है।
4. बेशक 2012 में भी एफआरबी को डिटेक्ट किया गया था। मगर, **हाल में विशाल गज्जर ने जिन एफआरबी को डिटेक्ट किया है, उनकी फ्रीक्वेंसी पहले से कहीं ज्यादा है।** इन्हें सुनकर ऐसा लगता है, जैसे इन्हें एलियन ने तो नहीं भेजा। बैकथ्रून लिसन प्रोग्राम के सदस्य और बर्कले एसईटीआई रिसर्च सेंटर के डाइरेक्टर एंड्र्यू सीमन के अनुसार इस सोर्स से पता लगे बर्स्ट के जैसी फ्रिक्वेंसी पहले कभी नहीं देखी गई।
5. ब्रेकथ्रून लिसन की ओर से इन 15 एफआरबी के बारे में कहा गया है कि हाल में खोजी गई इन एफआरबी ने दो बिलियन वर्ष पहले ही सोलर सिस्टम को छोड़ दिया था।
6. इन **15 रेडियो बर्स्ट विज्ञान के लिए नई खोज तो हैं ही, साथ ही ये एलियंस की संभावना को भी दर्शा रहे हैं।**

सरस्वती सम्मान

कोंकणी और मराठी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार **महाबलेश्वर सैल ने केके बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान को ग्रहण** किया है। उन्होंने कहा कि कोंकणी भाषा की **मूल भूमि गोवा है।** लेकिन, पुर्तगाली शासन के लंबे समय के दौरान यहां पर खास विकास नहीं हुआ। लेकिन, गोवा मुक्ति के पिछले 50-55 सालों में ही कोंकणी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की गई है। इस मौके पर **केके बिरला फाउंडेशन** की अध्यक्षा शोभना भरतिया ने बताया कि साहित्य के क्षेत्र में फाउंडेशन तीन बड़े पुरस्कार **सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार** संचालित करता है। इस मौके पर पर पुरस्कार चयन परिषद के सदस्य सचिव सुरेश ऋतुपर्ण ने प्रशस्ति पत्र का पाठ किया।

क्या है

1. **केके बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान साहित्य का शीर्षस्थ पुरस्कार माना जाता है।** पिछले दस वर्ष की अवधि में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
2. **केके बिरला फाउंडेशन इसके अलावा हिन्दी भाषा के लिए व्यास सम्मान व राजस्थान के हिन्दी-राजस्थानी लेखक के लिए बिहारी पुरस्कार प्रदान करता है।**

महाबलेश्वर सैल के बारे में

1. **कर्नाटक के कारवार के निकट माजाली गांव में 4 अगस्त 1943 को जन्में महाबलेश्वर सैल** का नाम कोंकणी और मराठी के वरिष्ठ लेखकों में शुमार किया जाता है। वे भारतीय सेना में भी काम कर चुके हैं।
2. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वह पंजाब की हुसैनवाला सीमा में तैनात थे। उनके चार मराठी नाटक और एक उपन्यास व कोंकणी में पांच लघु कथा संकलन व सात उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं।
3. लघु कथा संकलन तरंगां के लिए उन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार से 1993 में सम्मानित किया जा चुका है।